

जल प्रहरी

सम्मान समारोह-2023

स्मारिका / Souviner

Country Partners:



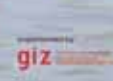
EMBASSY OF DENMARK
New Delhi



Knowledge Partners:



NIU
National Institute of Urban Affairs



Supporting Partners:



MAHARATNA



*creating opportunities,
energising lives.*

Bharat Petroleum's existing network of Retail Outlets comprises of over 21,000 petrol stations and continues to grow at a steady pace. Over 91 million households use Bharatgas for cooking. While hi-tech lubricants and industrial products keep the wheels of the nation moving, aviation fuels lift aircrafts to lofty heights. The group's three refineries at Mumbai, Kochi, and Bina produce environment-friendly fuels. With interests in exploration blocks across five continents, BPCL has a significant presence across the entire value chain.

Our diverse operations create numerous opportunities for existing and potential stakeholders to enhance profitability and growth.

We aim to collaborate, diversify and excel as we continue in our pursuit of excellence.

www.bharatpetroleum.in



CONTENTS

Name	Page No.
Forward by Shri Anil Singh	6
Article by Shri Ameya Sathaye	7
Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022	8
Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2021	13
Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2019	16
Article by Shri Parbatibhai Savaibhai Patel	20
Distinguish Jury Panel Jal Prahari Samman	21
Article by Shri Rajendra Singh, Waterman of India	22
Article by Indo-German Development Cooperation (GIZ India)	24
Article by Prof. Dr. A.K. Gupta	29
JAL PRAHARI	
Shri Ajay Sahay	30
Shri Arvind Saxena	32
Shri B. Murugesh (IAS)	34
Smt. Bedashree Choudhury	36
Shri Bhagwan Rana	38
Dr. (Smt.) Bhakti Lata	40
Shri Deepak Sahu	42
Shri Dilip Sakhiya	44
Shri Dhumman Singh Kirmach	46
Shri G. S. Priyadarshi (IAS)	48
Shri Girish Shah	50
Shri Gunvant Chindha Sonawane	52
Shri Jagdish Singh Negi	54
Shri Kuldeep Meena (IAS)	56
Smt. Laxmi Nagappan (IAS) / Smt. Saumya Pandey	58
Shri Manish Bansal (IAS)	60
Dr. (Smt.) Meena Jangid	62
Shri Nimal Raghavan	64
Shri Prashant Gadekar (IRS)	66
Shri Pulkit Khare (IAS)	68
Shri Rambabu Tiwari	70
Shri Ruhail Maqbool Sheikh	72
Shri S Krishna Chaitanya (IAS)	74
Shri S. Arumugam	76
Shri Sharad Agarwal	78
Shri Shekhar Narayanrao Nimbalkar	80
Smt. Shilpa Nag (IAS)	82
Smt. Shruti (IAS)	84
Shri Sunil Prabhakar	86
Col. Suresh Patil	88
Shri Vaijinath Jagannath Ghongade	90
Shri Yashu Deep Singh (IFS)	92



जल प्रहरी

सम्मान समारोह-2023

CHIEF GUEST

Shri Gajendra Singh Shekhawat

Hon'ble Minister of Jal Shakti

SPECIAL GUEST OF HONOUR

Shri Narayan Rane

Hon'ble Minister of MSME

GUEST OF HONOUR

Smt. Sadhvi Niranjan Jyoti

Minister of State of Consumer Affairs, Food and
Public Distribution, Rural Development

Shri Parbatibhai Savaibhai Patel

Hon'ble MP (Lok Sabha)
Chairman, Jal Shakti Committee

Shri Unmesh Patil

Hon'ble MP (Lok Sabha)

Shri Gopal Shetty

Hon'ble MP (Lok Sabha)

Shri Ramesh Bidhuri

Hon'ble MP (Lok Sabha)

Shri Parvesh Varma

Hon'ble MP (Lok Sabha)

Shri B.S. Seechewal

MP (Rajya Sabha)

H.E. Mr. Freddy Svane

Ambassador of Denmark to India

Shri Rajendra Singh

Hon'ble Waterman of India

SUPPORTING PARTNER



implemented by
giz
Business Development
for International
Cooperation AGG GmbH



PRINT PARTNER

पंजाब केसरी
www.PunjabKesari.com

नवोदय टाइम्स

OUTREACH PARTNER

**TALKING
PoINT**
COMMUNICATIONS

BLESSED BY



PRINCIPAL SPONSORS



COUNTRY PARTNER



EMBASSY OF DENMARK
New Delhi

KNOWLEDGE PARTNER



MANAGEMENT PARTNER



प्रस्तावना

जल, जलवायु और प्रयासों के प्रति हर स्तर पर सकारात्मक नजरिया है जरूरी



अनिल सिंह सागर
संयोजक,
जल प्रहरी समारोह

देश सीओपी की मेजबानी की ओर बढ़ रहा है। इन दिनों दो ही विषय जल एवं जलवायु अनुकूलन को लेकर चर्चा में हैं। इसमें एक धार्मिक दृष्टिकोण के साथ प्रकृति, जल सुरक्षा तो दूसरी प्रशासनिक पहल के सकारात्मक प्रावधानों के हल के प्रति नौकरशाही का नजरिया।

प्रकृति की दृष्टि और दर्शन आधारित सोच से ही जल तथा पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारतीय ज्ञान व्यवस्था को आधार बनाकर विश्वभर में धरती को पानीदार बनाने की कोशिशें हमें धरती मां के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति न केवल सचेत करती हैं वरन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रेरित भी करती हैं।

हाल ही में जारी भूजल भंडारण की रिपोर्ट से पता चला कि भूजल भंडारण में वृद्धि हुई है। यह बताता है कि हम प्रयास करें तो असंभव कुछ भी नहीं है। एक बार फिर भारतीय किसानों, जल विशेषज्ञों के अनुभवों ने पुनः भारतीय बौद्धिक क्षमताओं और सनातन परंपराओं की प्रासंगिकता सिद्ध की है। भविष्य में पृथ्वी में पर्यावरणीय संतुलन के लिए युवाओं को अपनी सनातनी परंपराओं की जड़ों की ओर लौटना होगा।

जल एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों तथा जागरूकता में निहित धार्मिक विचारधाराओं की गहरी सोच और प्रासंगिकता है इसे नकारा नहीं जा सकता है लेकिन यहां कहना भी जरूरी है कि धार्मिक विचारधारा के साथ-साथ जल संवर्धन, संरक्षण के प्रयासों को प्रशासनिक, कानूनी पहलुओं के समाधान की भी आवश्यकता होती है। भूगर्भीय जल की स्थिति और उसके संभावित समाधानों के लिए इन पहलुओं पर अमल तभी संभव होगा जब सभी विचारधाराएं कानूनी परख पर खरी हों।

हां, प्रश्न यह उठता है कि क्या सीओपी जैसे मंच से कही गई बातें जन भागीदारी और जन भागीदारियों के प्रयास प्रशासनिक, लालफीताशाही, काम को नकारात्मक नजरिए से देखने के रवैए से पूरी की जा सकेंगी? भारत की नौकरशाही में इन दिनों दर्जनों प्रयोग दिख रहे हैं। विशेषतौर पर जल प्रहरियों के तौर पर कई विशिष्टजन सामने आए हैं। आईएस, आईपीएस, आईआरएस जहां जल संरक्षण, संवर्धन में जुटे हैं तो वहीं ऐसे अमले की भी कमी नहीं है जो साधारण जन के जल, जंगल, जमीन के प्रयासों पर लालफीताशाही की रेखाएं खींचकर उसे रोकने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी मंशा बेशक अपनी नौकरी बचाने की हो लेकिन कम से कम प्रकृति के कार्यों को लेकर नजरिया बदलने का समय जरूर आ गया है।

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद
अनिल सिंह सागर

संपादकीय

जल की यह पहल शुरुआत है, नये सफर की..

भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है लेकिन आज भारत के दो तिहाई या 63% जिलों में भूजल स्तर गिरने का खतरा है आजादी के बाद से हमारे जल संसाधनों में 70% की गिरावट आई है इसलिए सरकार ने इसे गिरती प्रवृत्ति को पलटने के लिए 2019 में अटल भूजल योजना, आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने की मुहिम शुरू की गई है।



अमेय साद्वे
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
एवं संपादक

अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत 94000 से अधिक जल निकायों की पहचान की गई है जिनमें से 55887 जलाशयों पर काम शुरू हो गया है। इसी दिशा में जल अभियान जल से नल सहित कई योजनाएं ऐसी भी शुरू की जा रही हैं जिसके जरिए हर घर को पानी मिले और करीबन 11 करोड़ परिवार इस योजना से जुड़े भी हैं लेकिन क्या इन परिवारों को जल मिलने के बाद इनकी नजर में पानी का महत्व कम हो जाएगा क्योंकि अब वह उन्हें आसानी से सुलभ हो जाएगा। क्या जल स्रोतों से उन्हें पानी मिलता रहे इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। नहीं जल प्रहरी बनकर आप सभी इस पानी की आपूर्ति सतत बनाये रखने के लिए काम करें।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल सम्बन्धित कई अभियान, योजनाओं को चलाया जा रहा है, जल संरक्षण की दिशा में कई काम हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से जहां जल संरक्षण संवर्धन का हर व्यक्ति को साफ-सुथरा पीने का पानी मिले क्या हम देश के सरोवर जल स्रोतों भाव रखते हैं। सरोवर तालाब पर कब्जा पहले कूड़ा डालना फिर उस पर अपने पशुओं को भागना और धीरे-धीरे या तो उस पर मकान बना दिए गए या खेत बनाकर खेती शुरू कर दी गई यह विचार करने का प्रश्न है कि जो तालाब पोखर नदियां हमें जीवन देते हैं हम उन्हीं को कब्जा करके खत्म करने में जुटे हैं यह क्या मानसिकता है यह हमारी पानी के प्रति सम्मानजनक नजरिए को पीछे छोड़ता है हम जल व जल स्रोतों को अपने पुरुषों अपने देवताओं के तौर पर मानते रहे हैं इसलिए यह परंपरा आगे बढ़ाने का समय है हम आधुनिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं किंतु आधुनिकता से बढ़कर जीवन है और हर सांस के लिए स्वच्छ जल वायु धरती पर जीवन जीने लायक पर्यावरण की आवश्यकता है इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं हर व्यक्ति जल परी बनकर कम से कम अपने हिस्से के 200 लीटर पानी रोजाना को बचाने की मुहिम पर काम करें और धरती माता को उस पानी को लौटाए जिसका वह इस्तेमाल करता चला आ रहा क्योंकि यह काम सिर्फ किसी संगठन सरकार के जिम में नहीं छोड़ा जा सकता हम सभी को जोड़ना होगा मैं तो झूठ गया हूं और मुझे पता है आप भी शब्द उठ गए बस अब परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे जय हिंद।

अमेय साद्वे

जल प्रहरी सम्मान समारोह 2022 की झलकियाँ



Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022



Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022



जल प्रहरी सम्मान समारोह 2022 की झलकियाँ



Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2022



जल प्रहरी सम्मान समारोह 2021 की झलकियाँ



Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2021



जल प्रहरी सम्मान समारोह 2021 की झलकियाँ



Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2019



जल प्रहरी सम्मान समारोह 2019 की झलकियां



Glimpses from Jal Prahari Samman Samaroh 2019



जल प्रहरी सम्मान समारोह 2019 की झलकियां





जल, जन सरोकार का विषय है, सरकार के साथ जनता को मिलकर चलना होगा

- परबतभाई सवाभाई पटेल

संसद सदस्य (लोक सभा) बनासकांठा, गुजरात
सभापति जल संसाधान समिति

गुजरात में हर घर तक पानी पहुंचे, प्रत्येक जन को स्वच्छ पानी मिले इसके लिए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तभी भागीरथी प्रयास किए थे। सुजलाम सुलाम योजना के अंतर्गत मई महीने में पूरे गुजरात में तालाब खोदने का काम शुरू किया जाता है।

सुजलाम सुलाम योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता कि पानी की टंकी की स्काई करवाई जाए, नदियों की स्काई हो, पानी के दूसरे जल स्रोतों की स्काई के काम भी किए जाते हैं। इन सभी कार्यों में सरकार का योगदान एक विशाल प्रयास है लेकिन उन प्रयासों पर जो जमीनी अमल होना चाहिए वह 100 सौ प्रतिशत तभी होगा जब सरकार के साथ साथ जनता भी कदम बढ़ाए। जल संबंधी योजनाओं को भारत सरकार के साथ साथ राज्यों के जल निकायों की देखरेख, निगरानी में किया जाता है। गुजरात सरकार भी यह निगरानी करती है और जिले में जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं तथा हर एक गाँव में ग्राम समिति की रचना की गयी है जो समिति बनाकर इन कामों की निगरानी करती है। लेकिन कई बार ऐसा कुछ जगहों पर देखने में आया है कि गैर सरकारी संगठन पूरी ईमानदारी से इन कार्यों को अंजाम नहीं दे रहे हैं। हां, कुछ लोग जरूर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इसीलिए उसके असर भी दिख रहे हैं।

अच्छे कार्यों के करने वालों के प्रयास ही हैं कि जल की उपलब्धता, स्वच्छता बढ़ रही है। गुजरात सहित राज्य के कई इलाकों में ऐसा दिखता है कि जो पानी के प्रति जागरूकता होनी चाहिए ग्राम स्तर पर बनी समितियों को उसकी पूरी समझ नहीं है। मैंने कई गाँव का दौरा किया है दुर्भाग्य यह है कि वह पानी की एक-एक बूंद की कीमत नहीं समझते। नल खुला छोड़ देते हैं। हो सकता है अनजाने में रह जाता हो लेकिन यहाँ पर जागरूकता होना जरूरी है।

मैंने कई बार अपनी गाड़ी से उतर करके ये नल बंद किए हैं। कई बार टपकते हुए नलों को मिस्त्रे बुलाकर ठीक करवाया है।

पंचायत के अधिकारियों को आग्रह किया है कि भाई पानी के प्रति जागरूक करो, इसे व्यर्थ मत बहाओ। हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट भी आई है कि देश के कई राज्यों में भूजल स्तर बढ़ा है और मैं भी जब गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो कई जगह मैंने यह देखा है या देश के कई जगह पर जाता हूँ, देश के कई राज्यों से चुन कर आए सांसदों से बात करता हूँ तो वह भी यह बात मानते हैं कि पहले से भूजल बेहतर हुआ है। भूजल भंडारण बेहतर हुआ है और अटल भूजल योजना अपने पायलट प्रोजेक्ट के चरण में है। मैं पूरे देशवासियों से यह कहूँगा कि इस योजना को समझें, चूँकि यह अभी सात राज्यों में है लेकिन भविष्य में इसका विस्तार तय है। जिन राज्यों में इसकी जरूरत हो उन सभी राज्यों में इसको लागू करना चाहिए ताकि देश में पानी की उपलब्धता, स्वच्छता, हर व्यद्वि तक पहुँचाई जा सके। अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन के तौर पर भी बहुत कार्य हो रहा है ८

मैं सुबह से शाम तक जो भी जल का सेवन करता हूँ मैं चाहता हूँ कि उससे कई गुना समाज को वापस दूँ क्योंकि मैंने जल संसाधान मंत्री के तौर पर गुजरात राज्य की सेवा की है। आज लोकसभा की संसदीय समिति के चेयरमैन के तौर पर चाहूँगा कि जल संसाधानों का उचित, हर व्यद्वि के लिए उपयोग हो। मैं चाहूँगा कि देश के हर व्यद्वि को शु) पानी मिले और वर्षा जल संरक्षण किया जाए, भूजल स्तर बढ़े। अकेली सरकार इन कार्यों को पूरा नहीं कर सकती है लेकिन सरकार, सामाजिक सरोकार, बिजनेस संस्थानों, सरकारों को मिलकर हर योजना का पूरा लाभ जनता तक पहुँचाना होगा और जनता को भी उसी तरह उसे स्वीकारते हुए प्राकृतिक संसाधानों की रक्षा करनी होगी।

हमारी संसदीय समिति में सभी सांसद इस बात को भी ध्यान में रखते हैं और उसे उठाते भी हैं कि जन जागरूकता बहुत जरूरी है इसलिए आप सभी जागरूकता के साथ जल की प्रत्येक योजना पर नजर रखें। जल की हर धारा, स्रोत पर नजर रखें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कहते हैं कि पानी प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, इसको जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, व्यर्थ न जाए इसका संचय किया जाये।

JAL PRAHARI SAMMAN SAMAROH 2023

DISTINGUISH JURY PANEL



Justice S S Chouhan
Chairman

MEMBERS



Dr. D.K. Bhalla, IAS
Adviser to
Chief Minister of Nagaland



Dr. Atul Kumar Tiwary, IIS
Additioanl Director General
(AIR) Ministry of Information
and Broadcasting
Govt of India



Shri Yugal Joshi
Adviser, Water & Land
Resources, Communication;
& Mission Director, LiFE in
NITI Aayog



Dr. Ujjwalkumar Chavhan, IRS
Income Tax Department
Ministry of Finance



Shri Dalbir Singh
Deputy Secretary
Ministry of Jal Shakti



Shri Shiv Mohan Dixit
Advisor (Technical)
National Jal Jeevan Mission
Ministry of Jal Shakti



Shri Er MCT PAREVA, IES
Former Adg, CPWD Govt Of India
Chairman, Indian Institution of
Technical Arbitrators Delhi



Shri Giriraj Goyal (MES)
Former Director,
Ministry of Jal Shakti



Col. Shashikant Dalvi
Director, Parjanya, Rainwater
Harvesting Consultancy



BK Yeshwant Patil
Head-IT & Madhuban Radio
Brahma Kumaris, Mount Abu



Shri Anil Singh Sagar
Convenor,
Jal Prahari Samman

पुनर्जीवित अरावली अब पुनः विनाश की दिशा में है

वर्ष 2014 के बाद फिर से अरावली में अवैध खनन का काम तेजी से आगे बढ़ा। इस खनन ने अरावली को फिर से नंगा करना शुरू किया है। जिसके कारण फरीदाबाद का पूरा इलाका जो 1980-90 में खदानें बंद होने के कारण हरा-भरा होने लगा था, वे पहाड़ियाँ अब नंगी हो गई हैं। इससे राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं, अब दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगी हैं। इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि, अब अरावली फिर अपने पश्चिम की रेत को पूरब की तरफ लाने में मदद करेगी। दिल्ली के फेफड़ों का काम अरावली के जंगल करते थे, वह फेफड़े अब बेकार होकर, अरावली व दिल्ली को बीमार करेंगे। हमें यह समझने की जरूरत है कि, जिस प्रकार 1991 के बाद अरावली में खदानों को बंद होने से, अरावली पुनर्जीवित हुई और अरावली में जल संरक्षण का काम तेज हुआ था; वैसे ही अब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के लोगों को भी एक बार फिर करने व आवाज उठाने की जरूरत है। उस जमाने में भारत की संसद के लोकसभा अध्यक्ष स्वयं जापान लेने व अरावली बचाओ आंदोलनकारियों से मिलने आए थे। उसके 6 महीने के बाद ही सरकार ने कानून बनाकर, 7 मई 1992 को नोटिफिकेशन जारी किया था। अब फिर से अरावली बचाओ 1980 के आंदोलन को पूरे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में शुरू करने की जरूरत है।



जलपुरुष राजेन्द्र सिंह

मेरी आंखों में वर्ष 1980 में जयपुर की झालाना डूंगरी के खनन से नष्ट होती अरावली पर्वतमाला का कष्ट बहुत चुभ रहा था। जयपुर के भवन निर्माण कार्य अरावली के पत्थरों से ही हो रहे थे। झालाना डूंगरी, जयपुर के विकास के नाम पर विनाश का प्रतीक बन गया था। तब मैं भी खनन को विकास ही मानता था। 1988 में पालपुर गाँव के जन्सी मीणा, तिलवाड के गोपी कुम्हार और तिलदह के रूपनारायण जोशी व अन्य कई लोगों ने शाम के वक्त पूर पर आग तापते हुए कहा कि, खनन हमारे कुएं में पानी नहीं होने देगा। कुओं से ज्यादा गहरी खानें हैं। तुम जितना जल संरक्षण करोगे, वह सब खदानों में ही चला जायेगा। हमारे कुएँ तो सूखे ही रहेंगे। खदानों को बंद कराना, आपके बस की बात नहीं है। आपकी औकात नहीं है, खान मालिकों से लड़ना। वे तुम्हें मार देंगे या मरवा देंगे। इनसे जो टकराता है, वह नष्ट हो जाता है। खदान मालिक सोचते हैं, जब हम पहाड़ खोद सकते हैं, तो आदमी की औकात क्या जो हमसे टकरायेगा।

सभी में भय व्याप्त था, डर रहे थे। मैं, बिना डरे खनन बंद कराने में जुट गया। सबसे पहले नीलकण्ठ मन्दिर पर सभी का तीन दिन तक एक शिविर रखने हेतु, बैठक बुलाई गई। इसमें जितने बुलाए, उससे दोगुना ज्यादा लोग आए। जब शिविर शुरू किया, तो सब डरे हुए ही बात कर रहे थे। बातचीत के बाद ही तो हम कुछ करने की तैयारी करें। शिविर के अंत में तय हुआ कि, लोगों के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले खनन क्षेत्र में अखंड रामायण पाठ करेंगे; फलस्वरूप 22 स्थानों पर अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ। इसमें खान मालिक, वन विभाग, ग्रामीण सभी शामिल हुए। सभी ने अपनी-अपनी बातें अखण्ड पाठ से समय निकाल कर की। इसके बाद सभी को बुलाकर इसका प्रभाव जाना, समझा और अंत में पर्यावरण संरक्षण यज्ञ तय किया गया। भर्तृहरि में यह यज्ञ एक सप्ताह तक चला। पर्यावरण यज्ञ में भी सभी आगे आए। मैंने इस यज्ञ के दौरान पूछा कि, खनन से क्या बिगाड़ हो रहा है? इस पर लंबी चर्चा हुई। यज्ञ की अंतिम आहुति में खनन बन्द कराने का संकल्प हो गया। इस संकल्प में फतेह सिंह राठौड़ तथा कई अन्य अधिकारियों को मैंने बुलाया था, पर वन विभाग के अधिकारी नहीं आये। खैर वन विभाग की तरफ से बातों का जबाब नहीं मिला।

खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र सिद्ध करने में मुझे बहुत कठिनाई हुई। अंत में जब सिद्ध हुआ कि खनन क्षेत्र ही वन क्षेत्र है, तब उच्चतम न्यायालय से खनन बंद कराने का आदेश मिल गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कराना बहुत कठिन रहा, असंभव लग रहा था। मेरे ऊपर जानलेवा हमले होने लगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के सामने ही मुक्त जानलेवा हमला हुआ। उस समय के जिला अधिकारी की गाड़ी में, बैठाकर मुझे भेजा तो वह गाड़ी तोड़ दी गई और मुझे गंभीर चोटें आयीं। इसकी प्रतापगढ़, पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाने पहुँचा, तो मेरे साथ चल रहे अधिकारी रिपोर्ट लिखवाने से मना करने लगे। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने कहा कि, राजेन्द्र सिंह जी आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो माफ कर सकते हैं। तब मैंने कहा कि, मैं तो माफ कर दूंगा परंतु आप सभी न्यायमूर्ति, भारत सरकार व राजस्थान सरकार के उपस्थित अधिकारी कैसे माफ करेंगे। आप माफ करें।

तभी राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि, हम माफ नहीं करेंगे। हमारी वन भूमि पर कब्जा करने वालों ने राजेन्द्र सिंह के ऊपर हमला किया है। यह हमारी जमीन, हमारे ही वन विभाग को दिलाने का ही काम कर

रहे हैं, हमारा विभाग इनके साथ है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। फिर तब न्यायमूर्ति चुप हुए। तब जिला अधिकारी ने भी थानेदार से रिपोर्ट लिखने को कहा। रिपोर्ट में कुछ भी उलटा सीधा लिखवाते तो तत्कालीन प्रधान वन संरक्षक जोर-जोर से कहते थे कि, हमने हमलावरों को, हमला करते समय देखा है। उनका नाम भी बता दिया और मौके पर मौजूद हमलावरों को वहीं पकड़ा दिया था। उच्चतम न्यायालय में इस घटना को न्यायमूर्ति एड. राजीव धवन ने उठाया और हमलावर को सजा दिलाई। इससे खदान मालिकों में डर बढ़ गया और खदानें रुक गईं। उसके बाद खदान मजदूरों को तालाब, जोहड़ बांध बनाने के काम में लगा दिया। उस जमाने में हजारों जगहों पर जल संरक्षण का कार्य शुरू हो गया। मजदूर भी तरुण भारत संघ के साथ काम में जुट गए। आरंभ में खदान मालिकों ने मजदूरों को तरुण भारत संघ के खिलाफ भड़का दिया था, इसलिए वे काम पर आने से रुक गए थे। लेकिन जब खनन और मजदूरों के भविष्य का योग मजदूरों को समझाया गया, तो वे जल संरक्षण और खेती के काम में जुड़ने लगे। इस प्रकार उनमें मजदूर से मालिक बनने का भाव पैदा हुआ और हजारों मजदूरों को किसान बनना अच्छा लगने लगा था। उसके बाद तो बड़ी संख्या में किसान शिविरों में आने लगे थे। शिविरों में जल संरक्षण हेतु स्थान चयन से लेकर जोहड़, चौकडैम, एनिकट, बांध, बनाना सीखने लगे थे।

जब ये अरावली क्षेत्र के लोग जल संरक्षण करके, पानीदार बने तो, वे दूसरों को भी चंबल, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, धौलपुर आदि जिलों में गांव-गांव जाकर पानी का काम सिखाने लगे। खनन से लोगों का रुझान कम हुआ और खेती में बढ़ने लगा। इस प्रक्रिया से हिंसक समाज अहिंसामय बन गया। अब इन लोगों का पूरा जीवन चक्र बदलने लगा। यह बदलाव पहले लोगों में आया और फिर धरती पर भी बदलाव दिखने लगा। पत्थर फोड़ने को छोड़कर, अरावली के सफेद संगमरमर, डोलामाईट, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, यूरैनियम, तांबा सभी तरह के खनिज पदार्थ इस अरावली पर्वतमाला में मौजूद हैं। इन खदानों को बंद हुए 33 वर्ष हो गए हैं। जब इस पर्वतमाला को बचाने की न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की इच्छा दिखाई दी, तब खानमालिक भी अपनी खानों को बंद करने लगे और शांत हुए।

अरावली में जल, जंगल संरक्षण की यह प्रक्रिया 1991 में आरंभ हुई थी। इसी कारण जहां-जहां जल, जंगल, जंगली जीव, जंगलवासी और जैव विविधता संरक्षण कार्य हुए। वहां-वहां हरियाली बढ़ने व अरावली पर्वतमाला के पुनर्जीवित होने से जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और उन्मूलन के अच्छे काम समाज में और धरती के ऊपर स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। वर्ष 2014 के बाद से फिर अरावली पर्वतमाला के ऊपर संकट के बदल मड़ाने लगे। पहले अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदलने का दौर शुरू हुआ। उसके बाद 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली है, यह कहा जाने लगा। हमने कहा कि, पहाड़ों की पहचान उनकी ऊंचाई मात्र से नहीं होती, उनके मूल तत्व, बनावट, जैव विविधता आदि बहुत-सी जैवविविधता सामग्री की मौजूदगी से पहाड़ों की पहचान बनती है। सरकार अब सत्ता के उन्माद में संवेदनहीन होकर, उसे जो अनुकूल लगता है, वही करती रहती है। बहुत कुछ बोलने पर भी सरकारों ने नहीं सुना। अब तो भारत सरकार ने 10 किलोमीटर बाघ परियोजना से खनन की दूरी घटाकर 100 मी से 1 किलोमीटर तक की दूरी पर लाकर छोड़ा है। आजकल तो अरावली की वन भूमि को भी उद्योगभूमि में बदलने की पूरी स्वीकृति देना शुरू कर दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि, सरकार केवल उद्योगपतियों व खदान मालिकों के लिए ही काम कर रही है। भारत के वर्तमान और भविष्य की चिंता दिखाई नहीं देती।

भारत की आस्था तो पर्यावरण रक्षा है इसीलिए हम कभी पूरी दुनिया के गुरु थे। आजकल तो हम ही खनन करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा करने से हमारी पहचान भी हमारे पड़ोसी देशों की जैसे ही बन रही है, जो अपनी अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करने वाली विधियों के विशेषज्ञों के रूप में जाने-जाते हैं। भारत ने पूरी दुनिया में प्रकृति प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, आज वैसी पहचान नहीं रही। अब दुनिया के देश हमें भी प्रकृति के दुश्मन मानने लगे हैं, जबकि हम तो प्रकृति प्रेमी हैं। अरावली पर्वतमाला के साथ हमारे बुरे व्यवहार ने हमारी पहचान को दुनिया में बुराई की तरफ बदला है। अब बुराई में बदलने के सरकारी प्रयास और अधिक तेज हो रहे हैं, इसकी भारी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अरावली में अब विनाश कार्य तेजी से शुरू हो रहे हैं। उन्हें रोकना भारत की जनता के लिए बड़ी चुनौती है। अरावली विनाश की चुनौतियों को अवसर में बदलने हेतु जनता को ही तैयार होना होगा।

आज से 35 वर्ष पूर्व जब अरावली बचाओ आंदोलन की नींव डाली थी, तब मन में था कि, हमने अच्छा कार्य शुरू किया है, तो जनता भी आगे करा लेगी। हमने काम शुरू किया और अंतिम छोर तक लड़कर अरावली को बचाने की लड़ाई पहुंचाई थी, लेकिन अब वह उलट हो रही है। सरकार अरावली को बचाने के बजाय, उल्टा नष्ट करने के लिए कानून बना रही है। अब वन संरक्षण अधिनियम केवल अधिसूचित जंगल को ही जंगल मानेगा। 7 मई 1992, में अरावली को अरावली में सात तरह की भूमि, जैसे बीड़, बंजर, रखतबनी, राड़ा, रूंध आदि को वन भूमि माना था, उस पर भी अब शंका है। वन भूमि को व्यापारिक लाभ के लिए खुलेआम छूट देकर सरकार ने नई मान्यता “उद्योगपतियों की ही सरकार है-भारत की जनता की अब सरकार नहीं है।” स्थापित कर दी है, लेकिन काम करने के लिए भारत उद्योगपतियों के लिए उद्योगपतियों का देश हो रहा है, लोकतंत्र केवल नाम मात्र है।

अरावली की जल संरचनाएं, जंगल, जमीन सभी जगह बिगाड़ हो रहा है। इस बिगाड़ को रोकने हेतु न्यायपालिका के निर्णय की पालना करना, अब सरकार ने बंद कर दिया है। भारत की न्यायपालिका सर्वोत्तम कही जाती है, परंतु अब वह अपने निर्णय पालना करने में बहुत कमजोर पड़ गई है। वर्ष 2024 तक आते-आते अब पर्यावरण सुरक्षा हेतु लोग न्यायपालिका में जाते हुए भी डरने लगे हैं। न्यायपालिका अब बड़े लोगों और सरकारी साठ-गांठ की बातें अधिक सुनाने लगी है। न्यायपालिका तो भारत के गरीबों को न्याय दिलाती थी, अब केवल समझौते करती है। समझौते में तो सक्षम ही सफल रहता है, इसलिए अरावली के विनाश को देखकर भी लोग चुप हैं। मैं, जब भी न्यायपालिका के द्वार पर पहुंचा, देर तो हुई, लेकिन न्याय मिला है। तभी तो अरावली पर्वतमाला को बचाने हेतु उच्चतम न्यायालय से न्याय और भारत सरकार से कानून बनवाकर, राज्य सरकार द्वारा पालन करने में सफल रहा था। अब अरावली की गुहार कोई सुने और इसे बचाने के लिए आगे आए। अरावली का जंगल बचेगा, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पानीदार बनेगा। जंगल पानी को पकड़कर, धरती के पेट को भरते हैं, बादलों को बुलाकर बरसाते हैं। जब पहाड़ियों पर जंगल नहीं होता, खदानें होती हैं तो वहां गर्म हवायें चलने लगती हैं। बादल रूठ जाते हैं, बरसते नहीं हैं। तभी अरावली के गांवों के लोग लाचार, बेकार होकर शहरों की तरफ जाते हैं। अरावली का जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए अब अरावली के लोगों को 90 के दशक जैसा “अरावली बचाओ आंदोलन” ही खड़ा करना होगा। इस काम हेतु युवाओं को पानीदार बनने के लिए अरावली पर्वतमाला को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पुनः शुरू करनी होगी।



Implemented by

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Indo-German Development Cooperation (GIZ India)

Fostering Transformative Approaches for Green and Sustainable Development Partnership (GSDP) towards a Water-Wise World!



On May 2022, Prime Minister Narendra Modi and Federal Chancellor Olaf Scholz signed the German-Indian Green and Sustainable Development Partnership (GSDP), which gears cooperation between the two countries across different sectors towards the objectives of the 2030 Agenda and the Paris Agreement.

Context

Water is essential for all forms of life and any kind of social and economic development. The state of permanent water security supports poverty reduction and economic growth while contributing to improvements in social well-being and inclusive growth. However, the increasing water stress and global water demand has forced tough decision-making about the allocation of water resources.

The growing recognition of water as a finite and valuable resource, coupled with the increasing risks and impacts of water-related issues, has led to water insecurity being perceived as a threat to India's development and sustainability. India has 17.5 per cent of the world's population but less than 4 per cent of freshwater resources. 256 districts are water-stressed, and per capita freshwater availability is projected to drop to 1235 cubic meters by 2050. 30 per cent of Indian land is impacted by desertification and land degradation, and groundwater resources accounting for 62 per cent of irrigation water are also depleting extensively. Climate change, too has resulted in irregular monsoon patterns and increased frequency of natural disasters, causing further strain on India's water resources. Addressing these challenges is crucial for ensuring water security and sustainable development of the country.

Our Approach

In view of these challenges, the concept of Integrated Water Resources Management (IWRM) was placed on the international agenda in the run-up to the Rio Conference in 1992. It focused on the need for coordinated development and management of water resources and soils in the face of increasing and competing uses. The use of resources should be geared to the basic needs of people, the optimisation of water uses for economic development and the requirements of vital ecosystems. The Integrated Water Resources Management (IWRM) approach precisely pursues this goal. IWRM is regarded internationally as a model in the water sector and forms the basis for all our German Development Cooperation- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH water projects. These maxims of water management apply to national water catchment areas and river systems as well as to transboundary waters and aim at water resource security.

The GIZ Water Resources Security (WRS) Framework serves as a framework for implementing the IWRM mission statement. Within the framework, the GIZ orients itself towards an integrated policy approach that propagates a multidimensional system of objectives that aims at sufficient water resources for basic human needs, socio-economic development and sustainable ecosystems while simultaneously reducing water risks, preventing user conflicts and migration, considering the interconnected nexus between water, energy, food security and the environment.

Guided by the subsidiarity principle, the GIZ strengthens capacities for water resource management at all intervention levels: local water user associations, national catchment area management, the national water sector as well as cross-border river and sea area organisations and international water cooperation by supporting capacity development in the strategic fields of action towards:

- The development of a beneficial policy and a suitable institutional framework for the development and management of water resources
- The empowerment of organisations and people to put solutions into practice.

In recent years, GIZ has helped water authorities and water users in 22 countries (Afghanistan, Egypt, Bolivia, Grenada, Haiti, India, Yemen, Jordan, Kenya, Morocco, Nicaragua, Pakistan, Peru, Zambia, St. Lucia, Somaliland, South Africa, Tanzania, Thailand, Tunisia, Uganda, Vietnam) to improve water resource management and prepare for the challenges of climate change. We have also supported the establishment of river basin cooperation between the 2 to 10 participating riparian states in 15 cross-

border river basins. These include the following river basins: Mekong, Mono, Amu Darya, Amu Syr, Drin, Rio Arborito, Nile, Lake Chad, Niger, Congo, Cuvelei, Kunene, Limpopo, Zambezi, Orange-Senqu. Having carried out a large number of water, climate and environmental projects around the globe, GIZ draws on more than 60 years of experience in the field, which allows us to offer cross-sectoral, tailor-made solutions. Building capacity, resources and efficiency is a central element of our work, both in advising institutions and in working in partnership with government ministries, the private sector and grassroots organizations for jointly developed integrated solutions.

Building Momentum of Water Sustainability through Scalable Projects

Project Water Security and Climate Adaptation in Rural India (WASCA)

Commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by GIZ in partnership with the Ministry of Rural Development and Ministry of Jal Shakti in India, the Indo-German Technical Cooperation project aims at improving planning and financing mechanisms, demonstrating climate-resilient water management measures and strengthening cooperation with the private sector. The key processes include leveraging the digital potential of key public development programmes for planning and implementing water security measures. Further, the project strengthens the knowledge and capacity of government officials and the technical workforce on digital tools and integrated water resource management measures in all 15 agroclimatic zones covering 17 States/ UTs of India. Convergence with the government schemes (MGNREGA, Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, etc.) and multi-stakeholder collaborations are established for pooling technical and financial resources, as well as ensuring the sustainability of project activities.

Support to Ganga Rejuvenation (SGR)

With co-financing by the EU, the project supports the implementation and development of the India-EU Water Partnership. The project advises the National Mission for Clean Ganga at strategic and operational level to effectively manage the Ganga Basin. In cooperation with its partners, the project works on the development of Ramganga and Tapi River Basin Management Plans as well as Ganga Protection Plans at district level. These focus on implementing and monitoring clearly defined actions that address the most pressing issues in the respective area. Practical guiding documents and support in developing the relevant capabilities among local actor promote upscaling to other basins and districts.

Soil Protection and Rehabilitation for Food Security (ProSoil)

This project is helping smallholder farmers learn how to use climate-smart, agroecological methods to protect their land from soil erosion and restore and maintain soil fertility. To that end, it is offering training and guidance to both farmers and agricultural consultants. The project is also cooperating with governmental institutions and entities from the realms of science, research, the private sector and civil society to establish framework conditions that will promote change in agricultural and food

systems. The Project contributes towards community management of water resources.

Sustainable Aquaculture for Food and Livelihood (SAFAL)

The Indo-German technical cooperation project 'Sustainable Aquaculture for Food and Livelihood (SAFAL)' is part of the GIZ Global Programme on Sustainable Fisheries and Aquaculture (GP Fish). SAFAL aspires to provide more fish products and higher income from sustainable and resource-efficient pond-based aquaculture for the food-insecure population in Assam and Odisha. Under the umbrella of the Special Initiative "Transformation of Agricultural and Food Systems" BMZ, SAFAL operates in the sector of rural development and food security.

Developing Public-Private Partnerships (DevPPP)

Solving global challenges requires efficient cooperation among private and public sector actors. The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH has therefore been cooperating with companies through the develoPPP funding programme since 1997. The companies in question are often industry leaders and drivers of innovation in their particular fields. Joint projects connect the expertise offered by both sides. The companies bring their industry-specific knowledge, new technologies and creative approaches, while GIZ provides development policy expertise, skilled staff in the field and a global network encompassing policymakers, the private sector and civil society. One such notable example is the intervention of GIZ India along with private sector partners such as Symrise AG and Mars GmbH to sustainably strengthen the mint value chain in India considering water use efficiency under the SDG Compact Framework. The project is jointly implemented by Tanager, a US-based non-profit organization and GIZ India; works with multiple stakeholders and will be implemented in selected blocks of the Barabanki district of Uttar Pradesh in India wherein portable and automatic drip irrigation system was facilitated along with demonstration of solar powered drip irrigation systems.

Conclusion

The Indo-German partnership on water security stands as a testament to the collective commitment of both nations towards addressing one of the most pressing global challenges of our time. Through collaborative research, technological innovation, and shared knowledge, the two countries have forged a path towards sustainable water management practices that transcend borders. As we navigate the complex landscape of water scarcity and quality, GIZ serves as a beacon of hope, demonstrating that international collaboration is not only essential but also capable of producing tangible results. As both nations continue to exchange expertise and work hand in hand, it is evident that our joint efforts will contribute significantly to building resilient and water-secure societies, not only for their own citizens but for the world at large as it exemplifies the power of global partnerships in fostering a more sustainable and secure future for all.

More Information on GIZ India: <https://www.giz.de/en/worldwide/368.html>

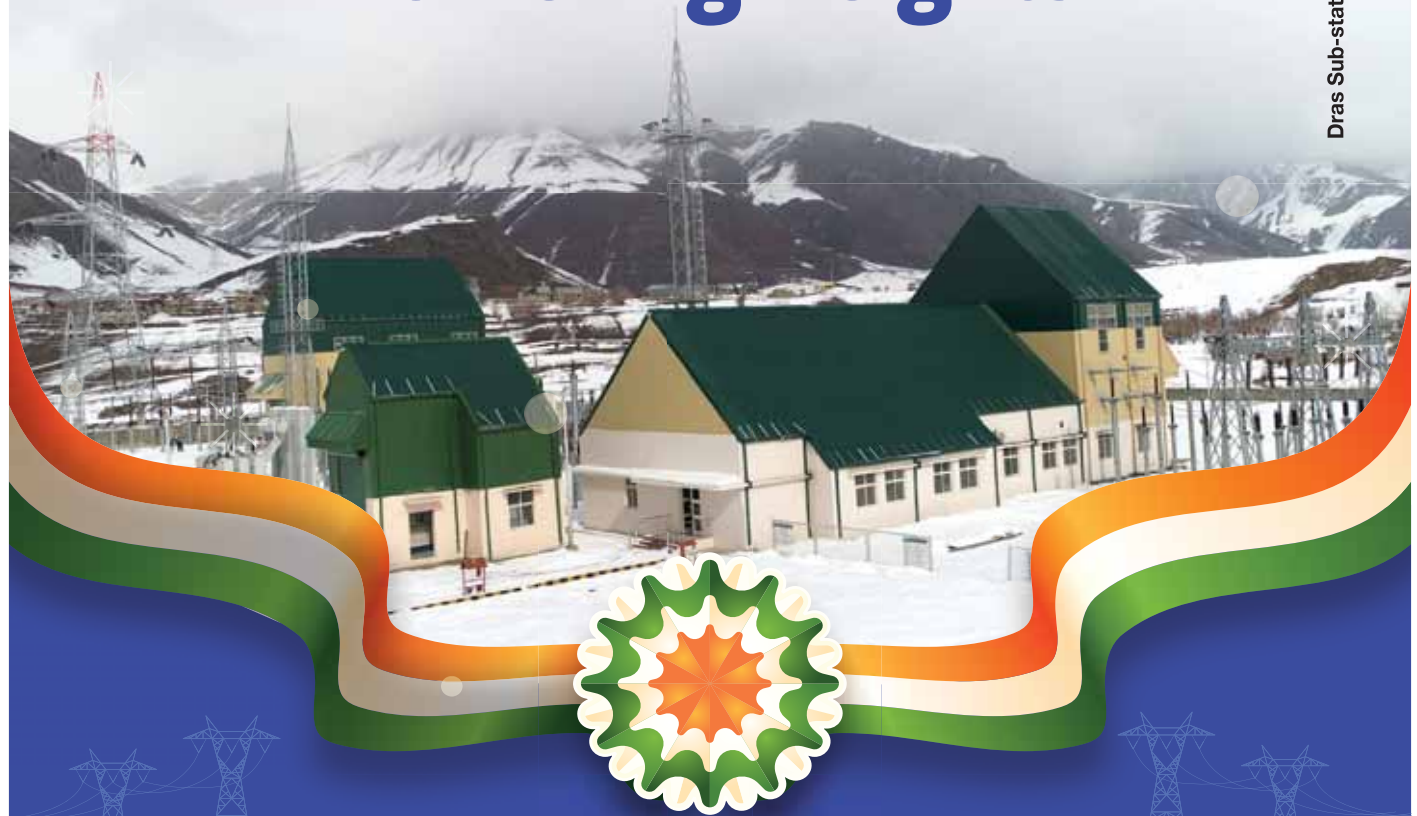


पावरग्रिड
POWERGRID



Powering Heights

Dras Sub-station, Ladakh



ONE NATION | ONE GRID | ONE FREQUENCY.

POWERGRID, a Maharatna Public Sector Undertaking (PSU) of Ministry of Power, Government of India, is one of the World's largest transmission utility engaged in project planning, designing, financing, constructing, operating and maintaining power transmission projects across India and having footprints in 23+ countries. It also undertakes operations in the Indian telecom infrastructure sector.

**TRANSMISSION
LINES >176, 109 CKM**

275 SUB-STATIONS

**TRANSFORMATION
CAPACITY
OF 512,001 MVA**

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Corp. Office : 'Saudamini', Plot No. - 2, Sector-29, Gurugram, Haryana - 122001

Regd. Office : B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016

CIN : L40101DL1989GOI038121

www.powergrid.in



Importance of Water in keeping a person Healthy Homeopathy for Health , Happiness and Harmony



It's common to hear that water is essential for your health. But why?

Water makes majority of the body weight. Its main Functions are

- Flushing out waste from your body
- Regulating body temperature
- Helping your brain function

One gets most water from drinking beverages, but food also contributes a small amount to daily water intake.

Ways water can help improve your well-being:

1. It helps create saliva As main component of saliva. Saliva also includes small amounts of electrolytes, mucus, and enzymes. It's essential for breaking down solid food and keeps mouth healthy.

2. It regulates body temperature Staying hydrated is crucial to maintaining body temperature. Body loses water through sweat during physical activity and in hot environments. Sweat keeps body cool, but body temperature will rise if not replenish the water lost. That's because body loses electrolytes and plasma when it's dehydrated.

3. It protects tissues, spinal cord, and joints Water consumption helps lubricate and cushion joints, spinal cord, and tissues. It helps enjoying physical activity and lessen discomfort caused by conditions like arthritis.

4. It helps excrete waste through perspiration, urination, and defecation Body uses water to sweat, urinate, and have bowel movements. One needs enough water in system to have healthy stool and avoid constipation. Kidneys are also important for filtering out waste through urination. Adequate water intake helps kidneys work more efficiently and helps to prevent kidney stones.

5. It helps maximize physical performance Drinking plenty of water during physical activity is essential. Athletes may perspire up to 6 to 10 percent of body weight during physical activity. Hydration also affects your strength, power, and endurance.

6. It aids in digestion Contrary to what some believe, experts confirm drinking water before, during, and after a meal will help your body break down the food you eat more easily and help digest food more effectively.

7. It helps with nutrient absorption In addition to helping with food breakdown, water also helps dissolve vitamins, minerals, and other nutrients from food. It then delivers these vitamin components to the rest of your body for use.

8. It helps lose weight. Studies show body fat and weight loss with drinking water in overweight girls and women. Drinking more water while dieting and exercising may just help you lose extra pounds. Water is important to nearly every part of your body. Not only will hitting your daily recommended intake help you maintain your current state of being, it may even improve your overall health.

Important- Carry a water bottle wherever you go so can drink whenever the need strikes. Keep track of intake. Aim to take in optimum amounts every day, a minimum of half the body weight in ounces. Pace yourself to approach half of your recommended consumption by midday. You can

Homeopathy for Health , Happiness and Harmony

Prof. Dr. A.K. Gupta, MD (Hom.)

Founder Director- AKGsOVIHAMS

President HMAI, Delhi State, M-7011842322,

Email- drakgupta@oviham.com, Website- www.oviham.com

जल स्रोतों के खड़े होने से किसान, जवान के साथ ही विलुप्त होते काले हिरण के चेहरों पर दिखने लगी चमक



अजय सहाय
कार्यक्रम अधिकारी, बिहार ग्रामीण विकास विभाग, मुजफ्फपुर, बिहार

रामपुर कला में 7 चेक डैम, 42 कि मी पुरानी एवं नई नहर का जिर्णोद्धार, सरकारी एवं निजी तालाब, सोख्ता, पक्का नाला का निर्माण, वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यों के द्वारा वर्षा के लगभग 4 लाख क्यूबिक मीटर जल का संग्रह से किसानों के चेहरे ही नहीं चमके, जंगली जानवर, विलुप्त होते काले हिरण की आबादी भी बढ़ रही है...यह सिलसिला जारी रहे..

बक्सर का रामपुर कला भीषण जल संकट से जूझ रहा था। वर्षा के लाखों क्यूबिक मीटर जल परिप्रेक्ष्य योजना के अभाव के कारण विभिन्न पईन, नहर से होकर कर्मनाशा एवं धर्मावती नदी में बह जाता। किसान देखते रह जाते। लगभग 4241 एकड़ की यह ग्राम पंचायत 500 बोरिंग के प्रयोग से भूमिगत जल दोहन में आगे थी, भूजल स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा था। छोटे किसान अपना आत्मविश्वास लगभग खो दिया था। आशा की कोई भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी।

जलशक्ति मंत्रालय के कैच द रैन अभियान अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता आधारित अभियान ने लघु एवं सिमांत कृषकों के दिल में आत्मविश्वास जगाया। वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव के आधार पर ड्रोन द्वारा हवाई सर्वेक्षण पारंपरिक जल निकायों के मान चित्रण के लिए ग्राम पंचायत-रामपुर कला में सामुदायिक भागीदारी से धर्मावती एवं कर्मनाशा नदी एवं नहर के भौगोलिक क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया।

डिजिटल इंडिया की मदद से आगे बढ़े और किसान गोष्ठी, रात्रि चौपाल, नुक्कड़ सभा, स्कूल में जागरूकता अभियान, वार्ड सभा द्वारा ग्राम पंचायत-रामपुर कला के जनता को जल संकट से लड़ने में मजबूत आधार दिया। करीबन 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए योजनाएं शुरू की।

रामपुर कला में 7 चेक डैम, 42 कि मी पुरानी एवं नई नहर का जिर्णोद्धार, सरकारी एवं निजी तालाब, सोख्ता, पक्का नाला का निर्माण, वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यों के द्वारा वर्षा के लगभग 4 लाख क्यूबिक मीटर जल का संग्रह कर 1500 एकड़ भूमि को कृषि योग्य भूमि की सिंचाई एवं 250 हेक्टेयर बंजर भूमि की सिंचाई कर कृषि योग्य भूमि बनाया गया। वर्षा जल कर्मनाशा एवं धर्मावती नदी में बेकार में बहने से बचाया गया। गर्मी के मौसम में हैन्डपम्प प्रभावी रूप से क्रियाशील रहते हैं जो पहले बंद पड़ जाते थे। विलुप्त जंगली जानवरों की संख्या बढ़ी और काले हिरण बढ़ने लगे और जल स्रोत वृद्धि से इनकी आबादी 800 से ज्यादा हो गई। धीरे धीरे ही सही लेकिन तस्वीर बदलने लगी है और यह सिलसिला जारी रहना चाहिए...।



जीआईएस ने सोने की रेत में दिखाई चांदी की बूंदें....

कैसे हुई शुरुआत...



अरविन्द सक्सेना
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण विकास विभाग
जयपुर, राजस्थान

राजस्थान जो सूखे और पानी की कमी से ग्रस्त है, यहां जीआईएस योजना ने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके, मनरेगा परियोजनाओं के शतप्रतिशत परिणाम सुनिश्चित करने में सहायता की। इसमें अग्रणी भूमिका में रहे जल प्रहरी अरविंद सक्सेना...

संपत्ति निर्माण और रखरखाव: मनरेगा का उद्देश्य उत्पादक संपत्ति बनाते हुए ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है। जीआईएस ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वाटरशेड-आधारित उपचार और उपलब्ध संसाधनों के लिए उचित रखरखाव, जल संचयन संरचनाओं, चेक बांधों और सिंचाई सुविधाओं आदि जैसी संपत्तियों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने में मदद की।

संसाधन मानचित्रण: जीआईएस का उपयोग जल निकायों, भूमि और वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण और मूल्यांकन करने के लिए किया गया। मिट्टी के कटाव, जलभराव या सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिली, जिससे मनरेगा के माध्यम से मिट्टी और जल संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने में मदद मिली।

परियोजना निगरानी: जीआईएस तकनीक मनरेगा परियोजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी करती है। प्रगति, खर्च, निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकती है। अधिकारी

सतत योजना: मनरेगा को जीआईएस के साथ जोड़कर परियोजनाओं का चयन करते समय पर्यावरण प्रिय कारकों, पानी की उपलब्धता और मिट्टी की स्थिति पर विचार करके टिकाऊ योजना बनी और उसके परिणाम दिखे।

सामुदायिक भागीदारी: जीआईएस मानचित्र ने मनरेगा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी दी गई। स्थानीय लोगों को समझाया, सुधार के सुझाव दिए, कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में प्रगति की निगरानी करने के लिए जीआईएस डेटा और मानचित्रों का इस्तेमाल किया।

प्रभाव का आकलन: जीआईएस योजना ने ग्रामीण समुदाय और पदाधिकारियों को ग्रामीण विकास संकेतकों पर मनरेगा परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम बनाया, इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पानी की उपलब्धता में सुधार और आजीविका में वृद्धि आदि।

निर्माण में रोजगार मिले, पानी आया तो मछली पकड़ने जैसे काम करने वालों को लाभ मिला। जल स्रोतों से भूजल स्तर बेहतर हुआ इससे किसान सूखे के दौरान भी फसलों की खेती कर सकेंगे। जल संरक्षण कार्यों में, महिलाओं ने विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला। नदी पुनर्जीवन से जलीय आवास और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ, जिससे स्थानीय निवासियों की आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई। कई नदियाँ स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं।



Water scarcity is history now, with improvement day by day...



B. Murugesh, I.A.S

Collector
District, Tiruvannamalai,
Tamil Nadu

Tiruvannamalai has a total population of 24.64 lakh and 6.3 lakh ha of geographical area. Of which 53% of the population depends on agriculture and 31 % of the land area is under agriculture. The average annual precipitation is 105 cm, of which 43 % occurs in southwest monsoon and 46 % in northeast monsoon.

The rapid urbanisation, industrialization and agricultural demands have a negative impact on ground and surface water resources. Immediate conservation measures and sustainable practices are imperative to safeguard this vital resource for current and future demands. District Rural Development Agency, Tiruvannamalai, Tamil Nadu completed a comprehensive Gram Panchayat (GP) level water resources management plan for 860 GPs and identified shelf of works projects in 2019-20 and started implementation through Mahatma Gandhi NREGS.

The science-based works identification in the GIS platforms enabled the field actions. The works between 2019-2023 focus on a set of relevant water harvesting and storage by managing surface runoff with both hard engineering structures and soft options mainly plantations. The impactful water harvesting storage and recharge structures are 1973 farm ponds in the fields of small farmers, 1643 recharge shafts, 12 gully plugs, 1321 check dams, 525 percolation ponds, 343 trench cuts, 125 water bodies restoration, construction of 189 open wells for small farmers, 30659 individual and 3866 community soak pits for managing grey water along with establishing 354 nurseries to raise quality saplings for plantation with locally suitable tree species, afforestation in 1490 sites along with innovative climate resilient measures like greening of hillocks in 6 sites, restoration of fallow lands in 8 clusters and silvi-pastoral systems in 29 sites.

Through these structures, more than 12,06,536 sq.m area was treated, which was largely in the common and public lands with an investment of around INR 3931 crore. Some of the relevant climate resilient measures that harvest, store and recharge water combine the hard and soft structures are given below: The greening of hillocks involves planting native vegetation on rocky terrains, transforming them into vibrant live ecosystems. It is a model that harmonises land, water, and vegetation ensuring a sustainable landscape management. Here a combination of activities is identified depending upon the slope gradient and ownership of the land. It was done in 68.5 ha of hillocks, treated with 4000 continuous contour trenches, planted 29972 trees, 6 gabion structures, 7 rockfill dams, 6 check dams, 8 percolation tanks, and 35 farm ponds with more than 100 ha under agroforestry plantations. Thus, it increases vegetation cover reduces soil erosion and siltation in water bodies and increases the groundwater recharge downstream.

Nearly 16 water conservation works were implemented with different structures, plantation and soil moisture conservation activities. The different water conservation and harvesting works have improved the ground water level. The results have shown a positive change. The 23 % safe firkha's have increased and 46 % over exploited firkha's have reduced to semi critical and critical during the past two years. In the pre-monsoon period, the levels have increased from 10 to 4 metres below ground level (mbgl), and during the post-monsoon period, from 2.98 to 1.94 mbgl.





Bedashree Choudhury
Director (Climate Action)
Xondhan Foundation
Bongaigaon, Assam

Assam, a state that experiences flood every year, and this jal praharee helps vulnerable and flood-affected communities because she worked in rajsthan also... she understand water issues, and provide guidance and support for local action and conservation.

Assam a land who face flood and drought

water conservation focusses on local capacity building and youth engagement in wetland rejuvenation, scientific testing and monitoring of lakes, wetlands, and freshwater bodies, indigenous water knowledge documentation, and awareness campaigns for water users.

Assam, experiences flood every year, many places water scarcity also required water conservation. Along with training on WASH (water, sanitation, and hygiene), flood response and preparedness, and wetland conservation, I sensitize women, youth, and young children on sustainable practices for water source protection and help them improve their local watershed through plantation of indigenous species. At present I am working on a project supported by UNICEF Assam for integrating climate change and environmental sustainability into WASH, through policy-level advocacy and water source sustainability.

This year, planned, organized, and conducted an 8-day climate campaign in Bongaigaon, Assam, for flood-affected plain tribes and indigenous communities where over 500 people gathered to exchange knowledge on the interrelated effects of climate action, water security, food security, and income generation. With a focus on local knowledge and expertise, we discussed ways to improve watershed health and flood resilience of the region through wetland rejuvenation, plantation, and livelihood strategies that allow for sustainable economies. We have been running a capacity building program in the area for 4 months, in which we have trained 400 young children for water and climate action through storytelling, workshops, after-school clubs, and local events, to involve them in community conservation efforts and nurture them as future water leaders.

Being a young water professional myself, I advocate for youth inclusion, engagement, and capacity building of the younger generations to lead water conservation efforts and help their communities achieve water security. In those lines, I volunteer at UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) in the Adaptation Working Group, where I organize and conduct capacity building programs for over 800 youth in ecosystem-based adaptation and sustainable water use. I am also involved in organizing podcasts for public awareness on nature-based solution for water resources and other pertinent issues such as microplastics pollution in water, through a Twitter podcast channel called WaterSpeaks, of the International Water Resources Association (IWRA).



कुओं में पानी के साथ-साथ लौटा सौंदर्य, पूजने लगे ग्रामवासी



भगवान राणा
अध्यक्ष, हम सोशन फ्रंट
दिल्ली

दिल्ली के उत्तर
पश्चिम जिले में स्थित
कुतुबगढ़ में दो-ढाई
दशक पहले कुएं,
तालाब देखकर लोगों
को खुशी मिलती
लेकिन यह गुम हो
गई, अब यह धरती
को कौन लौटा रहा है
ये कुएं, तालाब?

दिल्ली देहात के गांव में कभी कुएं और तालाब गांव की धरोहर हुआ करते थे। जिस गांव में ज्यादा कुएं, तालाब होते उस गांव की उतनी ही रौनक भी निराली होती। धीरे-धीरे गांव से सिमट कर ये कुएं, तालाब इतिहास के पन्नों में ही रह गए। बाहरी दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में भी ऐसे ही सालों पुराना पनघट वाला कुआं कभी बदहाली की मार झेल रहा था। गांव के कुछ युवाओं की नजर पड़ी और इसके दिन बदल गए, यहां कई ट्रॉली कचरा निकला और अब न सिर्फ या कुआं बेहद खूबसूरत नजर आता है यहां पानी से भूजल भंडार भी समृद्ध हुआ।

ग्रामवासियों के प्रयासों से ही कुतुबगढ़ ही नहीं, आस-पास के चार-पांच ऐसे कुएं, तालाब हैं जो बीते समय के साथ रखरखाव और जरूरतें खत्म होने के बाद समाज से दूर हो गए थे लेकिन इनका रंग रूप बदला तो अब यह कुएं एक बार फिर से जीवित हो उठे हैं।

प्राचीन कुएं व तालाबों के प्रयोग में न होने के कारण स्वरूप खोते जा रहे थे व विशेष कर वर्तमान में कुओं को संरक्षित करने पर कोई भी सरकार व संस्थाएं इस और ध्यान नहीं दे रही थी। तभी सुन्दर रूप से इनके जीर्णोद्धार की योजना बनाई। ताकि कभी जल नल से न आए तो कम से कम एमरेंजेंसी में ये जिंदा रहें। भूजल भंडार भी रहे। इन कुओं से पुनः जल अपने गागरों में भर सकें।

आने वाली पीढ़िया भी इन कुओं का यह सुन्दर प्रारूप देखकर आपने आपको अपने पूर्वजों के इतिहास से जुड़ा हुआ महसूस कर सकेंगी।

वह इन्हें संरक्षित करने का काम भविष्य में भी करें ताकि इसी प्रकार तालाब जो पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए न सिर्फ हमेशा उपलब्ध रहते हैं, गर्मियों में इनके नहाने में काम आने के साथ साथ बच्चों के तैरने व भू-जल को संतुलित रखने के काम आते रहेंगे। वैश्विक तापमान के बदलाव के दौर में यह प्रयास अब रंग ला रहे हैं। अब तक 8 जल स्रोत तैयार किए इसमें एक प्याऊ, चार कुएं व तीन तालाब शामिल हैं। हां, अब शादी विवाह में यहां कुआ पूजन का रस्म ग्रामवासी खुशी-खुशी कर रहे हैं।



जल संरक्षण, संवर्धन की निगरानी के लिए भी हैं टूल

जल संरक्षण की निगरानी के लिए स्कोरबोर्ड बनाया गया। यह स्कोरबोर्ड बताता है कि कितना जल संरक्षित हुआ ताकि दावों को सत्यता के पैमाने पर परखा जा सके। जलस्मृति की संस्थापक और वैश्विक जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. भक्ति देवी के नेतृत्व में जल संरक्षण स्कोरकार्ड को बनाया गया। यह उपकरण मौजूदा परिसरों (आवासीय और वाणिज्यिक), परिसरों, कंपनियों और शहरों की जल संरक्षण स्थिति का साक्ष्य आधारित त्वरित मूल्यांकन प्रदान करता है।



डॉ. भक्ति लता देवी
संस्थापक, जलस्मृति फाउंडेशन
दिल्ली

जल संरक्षण के दावों पर स्कोरबोर्ड एक मॉनीटर है। वह बताता है कितना जल संरक्षित हुआ ताकि दावों को सत्यता के पैमाने पर परखा जा सके।

यह मूल्यांकन ट्रैफिक लाइट के स्कोरबोर्ड की तर्ज पर करता है और इससे जल संरक्षण स्कोरकार्ड के साथ-साथ जल सकारात्मक कार्य योजना के रूप में सामने आता है ताकि उन सुविधाओं को फिर से स्थापित किया जा सके जो पानी से भरपूर बना सकें।

जलस्मृति के पास स्थानीय जल पहल को विकसित करने और पहल के आसपास स्थानीय समुदाय को संगठित करने के लिए स्थानीय सामुदायिक चौपियन्स को सलाह देने के कार्यक्रम भी हैं। जल चक्र साक्षरता सत्र आयोजित कर पानी को बढ़ाने के लिए चिंतन और व्यावहारिक डिजाइन पर ध्यान देते हैं। हरियाणा राज्य में अटल भूजल योजना में क्षमता निर्माण विशेषज्ञ के तौर पर भी कार्य जारी हैं।

जल संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में 25 वर्षों तक काम करने के बाद 2018 में भारत में स्थानांतरित होने के बाद से डॉ. भक्ति देवी के काम का सामाजिक प्रभाव उन लोगों की संख्या के रूप में रहा है जो साक्षर हो गए हैं और जल संरक्षण के समाधान को लागू करने में सशक्त हो गए हैं। इस तरह के प्रभाव में पूरे भारत में सैकड़ों युवा पुरुष और महिलाएं और सरकारी क्षेत्रों में लगभग 1000 लोग शामिल हैं जो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना पर काम कर रहे हैं।





BK had a check dam near to manmohinivan complex for ground water recharging. It is having capacity to store 50 Lac Ltr of water.



Deepak Sahu



Goswami Man Mohan

Anand Sarovar : The water requirement of Anand sarovar is fulfilled through borewells. The campus anand sarovar hosts 3 bore well which provides water for 5000 occupants. This campus does not need water to be transported from outside

Pandav bhawan The water requirement of Pandav Bhawan is fulfilled through bore wells. The campus pandav bhawan hosts 2 bore well which provides water for 500 occupants. This campus need water to be transported from outside in summer season .

Gian Sarovar The water requirement of Gyan Sarovar complex is fulfilled through 3 borewells. The campus anand sarovar hosts 3 bore well which provides water for 1200 occupants. This campus need water to be transported from nearby

Brahma Kumaris is having its residential campus in Talehti Abu Road and Mount Abu. The water department of Brahma Kumaris is very concerned about the water usage in the campus by its visitors. The department also realize that it's an opportunity to share awareness about the usage and importance of water conservation .

Soft Water Section

This section of water department deals with softening (removal of calcium, magnesium, and certain other metal in hard water). The presence of certain metal ions like calcium and magnesium principally as bicarbonates, chlorides, and sulfates in water causes a variety of problems. Hard water leads to the buildup of limescale, which can foul plumbing, and promote galvanic corrosion .

The resulting soft water is more compatible with soap and extends the lifetime of plumbing. Water softening is usually achieved using lime softening or ion-exchange resins.

The main requirement for soft water in the organization is for Steam preparation for Solar Cooking System . Boilers in kitchen for cooking Utensil Washing Machine

The soft water produced by softener is utilized for steam cooking system, where the water gets converted to steam which is utilized in Kitchen. Normal water was causing blockage of pipe by lime formation. Same thing happens with boilers. The utensil washing machine gets jammed if we use hard water.

Rain Water Harvesting Section

We at Brahma Kumaris are also trying to implement sustainability measures like Rainwater harvesting. As Rajasthan is frequently get affected by draughts, we also pay importance to ground water recharging.

1. Water collected from roofs of I Lac Sq/feet Diamond Hall for water recharging .
2. Rain water from various building of the campuses are routed towards rain water harvesting tanks.
3. In our farming campus Tapovan we have also created man made pond for water recharging.
4. We are maintaining a check dam near our Manmohinivan Complex



Check-dams play an important role in helping villages, farmers, environment, animals and common people.



Dilip Sakhiya

President
GirGanga Parivar Trust

80% of the rain falls into the sea. If it stops, the well-being of the farmer and the village will increase

The geographical structure of Saurashtra region is like an inverted saucer due to which large amount of rainwater flows into the sea. There are about 50000 check dams in Saurashtra which were built years ago to make beneficial use of this water, which are in very dilapidated condition and the check dams for rainwater harvesting need immediate repair, deepening and making higher as well as new ones. Maintenance of these check-dams is also necessary to raise the ground water level. Construction and maintenance of the dam is a Hard work and labour and financial support is required Mr. Dilipbhai Sakhiya along with his team of volunteers has taken up these responsibilities and established the Girganga Parivar Trust.

With the belief that 'Every drop of water is precious, because there is a life in every drop', Girganga Parivar Trust has embarked on a journey to save water by repairing and constructing check dams

and has so far completed the construction/repair of 125 check dams. 11111 It is aimed to build a check dam in future. The work of this trust has been honored and applauded by Hon'ble Chief Minister Mr. Bhupendrabhai Patel and State President of BJP Mr. C.R. Patil sahib has also visited and encouraged

Many nationalists, industrialists have also supported Girganga Parivar Trust to conserve and enrich Saurashtra region, following Hon'ble Prime Minister Saheb's vision of water conservation and development to create 75 lakes in every district, the owner of Balaji Wafers has constructed "Heeraba Smriti Sarovar" named after Saheb's mother.

The storage of water is very beneficial especially for agriculture and farming as well as for animals, and birds. Especially Gujarat and Saurashtra have rocky and hilly terrain, 80% of the rain falls into the sea. If it stops, the well-being of the farmer and the village will increase

તૂટેલા ચેકડેમના દ્રશ્યો



ગીરગંગા પરીવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા ચેકડેમ ઊંડા થતા દ્રશ્યો



ગીરગંગા પરીવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા થયેલા કામના દ્રશ્યો



ગીરગંગા પરીવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા થયેલા કામના દ્રશ્યો



ગીરગંગા પરીવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા થયેલા કામના દ્રશ્યો





धूमन सिंह किरमच
उपाध्यक्ष, हरियाणा सरस्वती
विरासत विकास बोर्ड
कुरुक्षेत्र, हरियाणा



मुनीश बब्बर
अधिसापी अभियंता, विरासत विकास बोर्ड
कुरुक्षेत्र, हरियाणा

हरियाणा में पानी के लिए
ट्यूबवेल की गहराई बढ़ाना सबसे
पहला काम है लेकिन अगर
सरस्वती मेहरबान हो जाए तो ज्ञान
संभव है

और ज्ञान, विज्ञान से मुनीश
बब्बर ने कर दिखाया एक असंभव
काम...

सरस्वती नदी को पुनर्जीवन
मिला तो रास्ते के 125 गांवों को
पानी मिल गया। हजारों किसानों
को सीधे लाभ मिला तो उनके
खेत ही नहीं लहलहाए, चेहरों पर
मुस्कान खिल उठी...।

सरस्वती को हुए समर्पित तो हरियाणा में बह निकली दूध की धारा

पौराणिक नदी सरस्वती के पुनरुद्धार की चुनौती...

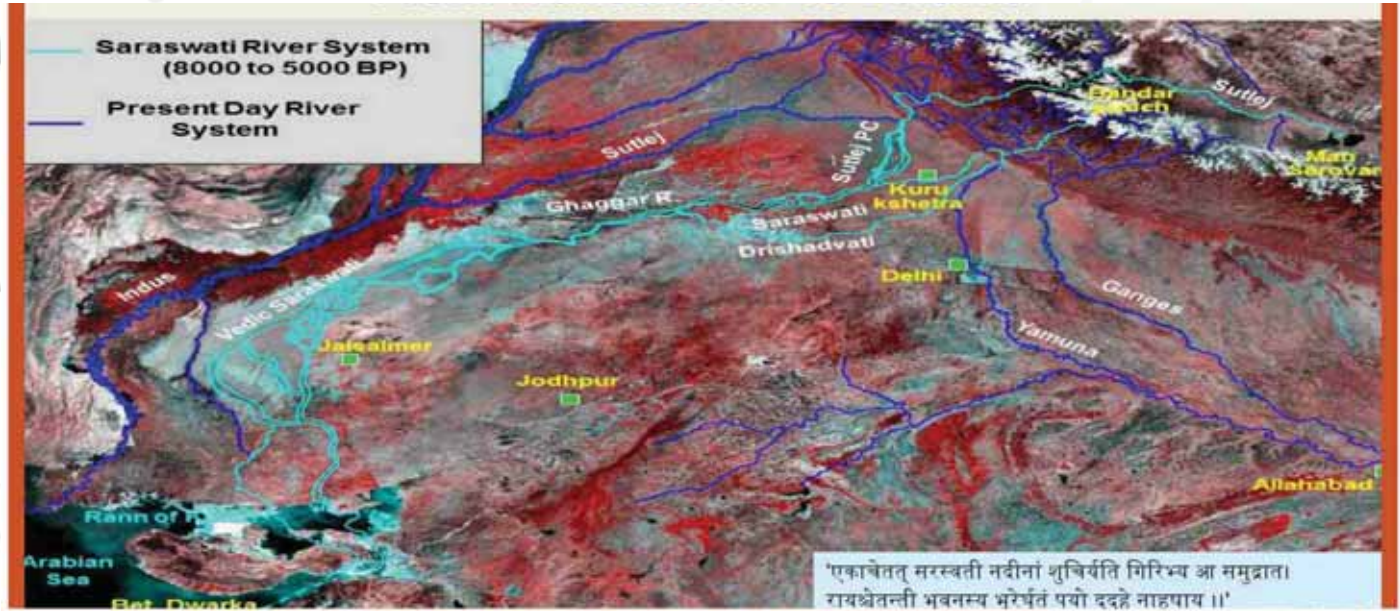
नदियों का बनना और लुप्त होना एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना है। इसे हाथ से बेशक
न बनाया जा सकता हो लेकिन कार्याकल्प किया जा सकता है। सरस्वती नदी के पुनर्जीवन
से हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि हिमालय से कच्छ के रण तक सरस्वती नदी के पुराने
मार्ग, संरेखण की पहचान।

सरस्वती नदी की सभी प्रमुख एवं छोटी सहायक नदियों की पहचान, सरस्वती बेसिन
को उसकी सभी सहायक नदियों के साथ चित्रित करना, बेसिन की नदियों को आपस में
जोड़ना। जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, सरस्वती नदी के संरेखण पर घाटों और जलाशयों
का निर्माण। नदी के किनारे सर्विस रोड का निर्माण, सरस्वती नदी के पुरापाषाण चैनलों का
विकास। जल प्रदूषण में कमी, सरस्वती नदी बेसिन का वास्तविक समय बेसिन प्रवाह अध्ययन,
जल संतुलन अध्ययन, नदी के भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान, पुरातात्विक और अन्य वैज्ञानिक
पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास। पुरातात्विक स्थलों की खोज, उत्खनन एवं विकास।
सरस्वती तीरथों का विकास, सांस्कृतिक एवं विरासत मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास।
नदी के बेसिन में वन क्षेत्र में वृद्धि, सरस्वती पर्यटन सर्किट का विकास।

हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों
के पुराने मार्ग/संरेखण की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है, जिसे हरियाणा सरकार
द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। 30 जुलाई, 2018 से नदी के पुनरुद्धार और जल संचयन
संरचनाओं, घाटों, तीरथों के निर्माण, पुरातात्विक स्थलों के विकास और उपरोक्त सभी पहलुओं
पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मानसून सीजन के दौरान सरस्वती नदी में पानी के
प्रवाह को बनाए रखने में सफल रहे और बाकी पूरे साल पानी के निरंतर प्रवाह को बनाए
रखने के लिए आदि बंदी पर बांध के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। ग्राम रामपुरा, बेहोली
और मर्चरी में सरस्वती नदी से जुड़ने वाले तालाबों के निर्माण से भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने
में मदद मिली है, जिसे सरस्वती नदी के मार्ग पर अधिक संख्या में तालाब विकसित करके
बढ़ाया जा रहा है।

सामाजिक प्रभाव...

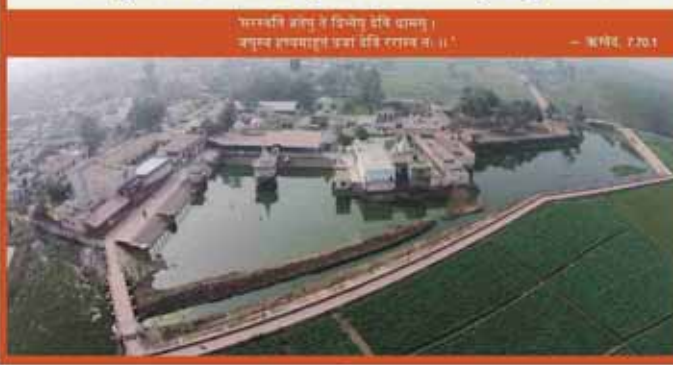
सरस्वती नदी के मार्ग पर पड़ने वाले सभी गांवों यानी लगभग 125 गांवों को सरस्वती
नदी से पानी रिचार्ज होने से लाभ हुआ और पिछले दो वर्षों में लगभग 2500 किसान
लाभान्वित हुए क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी खेती में स्थापित ट्यूबवेलों की गहराई
बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।



सरस्वती नदी तट पर प्राचीन धरोहर



सतयुगी सरस्वती तीर्थ, सरस्वती नगर, यमुनानगर



ngam Ghat recovered near Sara



आदिबद्री, एरियल व्यू



सरस्वती तीर्थ, पिहोवा



'सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।
आसद्यास्मिन्बहिषि मादयध्वमनमीना इष आ धेह्यास्मे ॥' - अथर्ववेद, 18.1.42.

जमीन पर उतरी योजनाएं तो सरोवर, तालाब, नदी हुई जीवित, पोर्टल पर दिखेंगे जल स्रोत

सरकारी योजनाओं से खड़े किए जल स्रोत, तालाब, अमृत सरोवर और कई नदियों को मिला जीवन। एक नहीं कई योजनाओं के सहारे ये सफर जारी है...

मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संचयन के लगभग 8.5 लाख काम हुए हैं। जल संबंधी कार्यों पर 14000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। जल संबंधी कार्यों के कुशल क्रियान्वयन एवं पारदर्शी निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का जीआईएस प्लान तैयार कर अपलोड किया गया है। अमृत सरोवर- भारत सरकार से प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य था और 15 अगस्त 2023 तक राज्य में कुल 5625 अमृत सरोवर बनने थे लेकिन 15 अगस्त 2022 की 1150 के लक्ष्य के मुकाबले 8133 अमृत सरोवरों पर काम शुरू हो चुका था।



जी.एस. प्रियदर्शी, आईएएस
आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

योजना जमीन पर उतरे, उसका फल जनता को मिल जाए यही उसकी सफलता है। लेकिन इसके पीछे प्रयास करने वाले ही जल प्रहरी होते हैं... ऐसे ही प्रयास किए हैं आईएएस अधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने...

यह कारवां यहीं नहीं रुका यूपी अमृत सरोवरों की संख्या के मामले में देश में नंबर 1 बना और 15 अगस्त 2023 को 13198 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन पर ध्वजारोहण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, हमने 9000 से ज्यादा और स्थानों की पहचान की है, जहां जल्द ही निर्माण शुरू होगा। हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक अमृत सरोवर देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा से राज्य में योजना को एक साल के लिए बढ़ाया ताकि अमृत सरोवरों को विकसित कर सकें।

यह सरोवर राज्य की पंचायती राज, भूजल विभाग, जिला खनिज निधि और यहां तक कि कुछ स्थानों पर सीएसआर से भी फंडिंग से बने हैं। राज्य में छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली आदि कई पारंपरिक त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाये गये और इसमें अमृत सरोवर मुख्य केंद्र बन गए हैं।

वर्ष 2022-23 में अमृत सरोवर के अलावा 11882 तालाब मनरेगा के तहत विकसित किये गये हैं। जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही के लिए राज्य में तालाबों का डिजिटल डेटा होना आवश्यक है। इसके लिए वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग तथा राजस्व विभाग के समन्वय से पोर्टल विकसित कर रहे हैं।

प्रदेश की 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में 484 तालाबों के निर्माण, 894 वृक्षारोपण संबंधी कार्य तथा 86 जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर 1250.23 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है।

छोटी नदियों का पुनर्जीवन-नदी में पानी का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह हो इसके लिए दो वर्ष में बाराबंकी में कल्याणी नदी, फतेहपुर में नून नदी, मिर्जापुर में कर्णावती नदी, आगरा में उटगन नदी, अरिंद नदी और फिरोजाबाद में आवा नदी। जालौन में नून नदी, प्रयागराज में वरुणा नदी, सहारनपुर में कृष्णा नदी, कन्नौज में अरिंद नदी, ललितपुर में बनई नदी और हरदोई में सई नदी आदि को पुनर्जीवित किया गया है।

मनरेगा योजना के अलावा इस कठिन कार्य को करने के लिए शायद ही कोई अन्य धनराशि उपलब्ध थी। इसलिए लोग यह देखकर बहुत खुश हुए कि सरकार इन लुप्तप्राय नदियों को पुनर्जीवित कर रही है। नदियों के अलावा बड़े तालाबों को भी मनरेगा योजना से पुनर्जीवित किया गया है।



जल, जंगल, जमीन के प्रति समर्पण : प्रकृति को समर्पित किए उसके आभूषण



गिरीश जे. शाह
प्रबंध न्यासी, समस्त महाजन,
मुंबई-महाराष्ट्र, राजस्थान,
गुजरात, मध्य प्रदेश

राजस्थान, गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
के नालों, तालाबों,
नदी, झीलें, नहरों
से आखिर क्या
हटा दिया जाए जो
किसान, ग्रामवासियों
की तकदीर बदल
जाए, समस्त महाजन
ने यह कर दिखाया...।

देश भर के सभी नालों, तालाबों, नदी, झीलें, नहरों को उनके मूल स्तर पर साफ किया जाए और गाद निकाली जाए। इसके एक प्रयास में दो लाभ मिलेंगे। पहला, झील (तालाब)-सीवर (नालों) से गाद हटाने से, जल भंडारण क्षमता और वर्षा जल का पुनर्भरण बढ़ गया है। दूसरा इस प्रकार निकाली गई गाद पास के खेतों में डालने से कृषि भूमि उपजाऊ बन जाती है।

कच्छ में और वर्षा जल संचयन, घास के मैदान के विकास के साथ 43 गांवों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यदि कच्छ के सभी 994 गांव पूरे हो जाएं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है।

कार्य का सामाजिक प्रभाव और कितने लोग लाभान्वित हुए

महाराष्ट्र के 556 से अधिक गांवों, राजस्थान के 200 से अधिक गांवों, गुजरात के

150 से अधिक गांवों में जल संसाधन विकास, जल संरक्षण कार्य से लाखों लोग लाभान्वित होते हैं।

महाराष्ट्र जल संरक्षण कार्य 330 जालना, 70 पालघर-वाडा, बीड्स और 46 अंबाजोगाई आदि सभी 356 से अधिक गांवों में काम किए गए। इसके साथ ही 285 जगह नाले खोले गए, 99 तालाब कार्य, दो नदियों पर काम किए, कुंडलिकासेना सहित कुल भूमि 4210 एकड़ में काम किए गए।

गुजरात के भुज, मुंद्रा, पालिताना, भावनगर, बनासकांठा-पाटन, कच्छ के लगभग 150 से अधिक गांवों में यह काम किए गए। राजस्थान के पाली, जोधपुर, आदि के सभी 200 से अधिक गांव में यह काम किए जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के गांवों में भी काम शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काम शुरू किए जा रहे हैं।



- कुल 52,092 एकड़ भूमि हरी-भरी हुई, गौचर बनाए गए
- कुल 435 झीलें को विकसित/साफ/गहरा करवाया
- गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के 554 गांवों में रैन वाटर हारवेस्टिंग करवाई
- सात नदियों, 18 कुंओं को विकसित करवाया
- हरियाली से पानी बचेगा इसी विचार से 86,600 वृक्ष खड़े करवाए
- करीबन-80 करोड़ रूपए खर्च किए गए



“Bhujal Abhiyan”



**Gunvant Chindha
Sonwane**

Seva Sahayog Foundation

**We have started
water conservation
work in the 2018
in 40 villages
of Chalisgaon
taluka of
Maharashtra with
the movement
called as “Bhujal
Abhiyan”.**

We have started water conservation work in the 2018 in 40 villages of Chalisgaon taluka of Maharashtra with the movement called as “Bhujal Abhiyan”. This is complete people movement, started with the aim of creating water literacy and increase the groundwater level. In all the 40 villages we have created water committee called as “Bhujal water committee” which has active 10 male/female members. All this active members have monthly meeting in the village where they discuss about availability of water, challenges, crop patterns, upcoming water conservation work and planning. This has been practice now in almost all villages where Bhujal Abhiyan is working. And then we have one level up meeting to discuss and understand the work of all villages. Each village water committee has 1 main person called as Bhujal Dindi Pramukh- like this there are 40 Bhujal Dindi Pramukh from 40 villages .Every Sunday Bhujal Abhiyan Dindi Pramukh have online meeting to discuss the work, plan and understand the challenges and solution.

We takes water literacy sessions in villages to understand the water cycle and understand the importance of water, groundwater and encourage people to save/ store each and every drop of water. To do this session we takes help from experts. Bhujal Abhiyan carries the shivar feri in villages to study and understand the watershed of village and believe in implementing water conservation work after only understanding the geology and watershed of village. Hence our work is proven as sustainable work, in that people, farmer’s contribution is very

much important. In all our work we have not taken any funds from govt. All the quality work have been done with the help of CSR and people contribution which is mandatory. The impact of Bhujal Abhiyan work in last 6 years is –

- We have created around 8 million (800 Crore liters) water storage capacity. Around 70000 farmers are benefitting by our water conservation and water management work. Farmer’s income per year per acre has been increased to Rs. 10000 to Rs. 20000.
- We have created 21 lakes in 16 villages with the people contribution and CSR help. Groundwater level has been increased by 2 meters in those villages.
- Around 52 KM nalla widening, deepening, river cleaning work has been done in 14 villages.
- Compartment bunding has been done on more than 50 hectors to stop the soil erosion.
- In 3 villages we have implemented mini watershed it includes CCT’s, Deep CCT’s, Gabion bunds, Compartment bunding work with people contribution
- Milk production is increasing in these villages where we are doing water conservation work. Also milk cattle’s are also increasing the villages.
- Migration is reducing in the villages because they have water available in the village for farming and because of that their kids are also attending the schools on a regular basis.
- By our work Soil quality is also improving in the villages and we have seen the good results in farm yields.
- We are nurturing more than 40000

- trees in 5 villages of Chalisgaon taluka to mitigate climate change and increasing the carbon credit.
- In 6 villages 500 farmers' couple are nurturing 2500 fruit trees. We have donated 3 trees and they have contributed 2 trees this way this 500 farmer couple are taking care of 25000 trees in their villages and in farms. Eventually this trees will produce fruits which will create extra income and help for climate change control.
 - We have created around 26 KM farm side roads in 11 villages, by that we have resolved 50 years old issue of farmers to reach their farms easily.
 - Bhujal Abhiyan is also working with 33 govt. primary schools for tree plantation where we are implementing "1 kid 1 tree" and creating awareness among the parents and student by planting tree/saplings.
 - We are also empowering woman with water conservation work by giving livelihood trainings like goat farming, poultry, and murgas. We are closely working with around 150 woman where not only we have provided trainings but also we have given the goats to them, so their migration is completely stopped now and they are getting employment in the village itself.
 - Last but not least – drinking water issue is also getting addressed in many of the villages where our movement is working.
 - Animal drinking water issue is also addressed because of our lake rejuvenation work Appreciation for our work.
 - United Nations Org (UNO) has taken consideration of our water conservation work and give us an opportunity showcase the work by a video in their High Level Political Forum (HLPF) program at New York City.



स्कंदपुराण की पवित्र उत्तरवाहिनी शिप्रा बन जाए बारहमासी

स्कंदपुराण में जिस नदी का उल्लेख है उसे मानवीय चूक से मृतप्राय कर दिया। पालिकाएं कचरा फेंक रही हैं, बस शुरूआत हुई है जिसके परिणाम सुखद हैं, अभी बहुत दूर जाना है..।

दिनांक 11 अक्टूबर, 2015 से शिप्रा कल्याणार्थ भवाली की शिप्रा नदी को साफ करने का अभियान शुरू किया गया। हर हफ्ते रविवार को सफाई अभियान चलाया गया। लगातार ढाई साल तक हर सप्ताह अभियान चला। शुरू में कुछ सप्ताह स्थानीय लोग और नगर पालिका ने सहयोग किया। हमने हर सप्ताह कुछ स्थानीय लोगो और 8 से 10 सहयोगियों को लगाकर उनके साथ दिन भर नदी को साफ किया। नदी से करीब 100 ट्रक कूड़ा कचरा निकाला, नगर पालिका को सौंप दिया।

सबसे पहले वहां से कचरा निकाला जहां लोगों और नगर पालिका ने नदी किनारे कचरा फेंका था। आसपास के लोगों से अपील भी की कि वह कचरा ऐसे न फेंके। लोगों में जागरूकता आई और नदी में कूड़े कचरे की मात्रा कम होने लगी। वर्ष 2017 में तो 6 महीने तक तीन सहयोगियों के साथ रोज नदी को साफ किया गया।

इसके बाद बीस साल से बंद जनेऊ शुरू करवाए, भवाली में देवी मंदिर के समीप सीधे नदी में गिरने वाले सीवरों को बंद करने का प्रयास किया और जिलाधिकारी के सहयोग से 150 से ज्यादा ओपन सीवर नदी से हटे और उनके लिए सीवर पिट बने। सरकार की ओर से शिप्रा को पुनर्जीवित करने वाली नदी में चुन लिया। अब नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए 13 करोड़ 45 लाख की योजना बनी है। प्रथम चरण में कुछ काम हुए हैं।

बाबा नीब करोड़ी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से यह रास्ता दिखा। ये नदी एक उत्तरवाहिनी नदी है। उत्तरवाहिनी नदियां बहुत कम होती हैं। उत्तरवाहिनी नदियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्कंदपुराण के मानस खंड में शिप्रा नामक नदियों का उल्लेख आता है। भवाली शहर की पानी की आपूर्ति शिप्रा नदी के जल स्रोतों से ही होती है। श्यामखेत में नांतीन बाबा आश्रम के आस पास इस नदी का उद्गम माना जाता है लेकिन मानवीय लापरवाही और अत्यधिक निर्माण कार्य होने से ये नदी फिलहाल एक बरसाती नदी भर रह गई है। करीब 22 या 23 साल पहले नदी में 12 महीने पानी रहता था अभी भी यदि इसमें कार्य सही ढंग से हो जाए तो इस नदी को निश्चित रूप से बचाया जा सकता है। यहां भारी मात्रा में कचरा इसी नदी में फेंका जा रहा है।

शिप्रा नदी के एक मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र में घोड़ाखाल के समीप करीब 250 खाल, खंती, छोटे तालाब बनाए गए हैं। जिनके द्वारा पिछले चार सालों में करोड़ों लीटर वर्षा का जल भूमि के गर्भ में गया है। इस क्षेत्र में करीब 40 हजार जलवर्धक वृक्ष जैसे बांज, बुरांश के फल आदि लोगो द्वारा काट दिए गए लेकिन उन काटे हुए वृक्षों की जड़ों से नई कोपले निकल आई है। ये कोपले भी प्रतिवर्ष लगने वाली आग के कारण जल जाती थी। क्योंकि इस जंगल में 100 प्रतिशत चीड़ के पेड़ हैं। अब यहां अच्छी हरियाली हो गई है। इन कोपल से छोटे छोटे झुरमुट टाइप के जंगल बन गए। ये झुरमुट वर्षा के जल को भी निश्चित रूप से ज्यादा मात्रा में अपने भीतर संग्रहित कर रहे हैं। यहां पर शिप्रा कल्याण समिति लगातार जंगल को हर वर्ष आग से बचा रही है। इस जगह समिति द्वारा वृक्ष रोपण भी किया गया है। वृक्षों की देखभाल भी की जा रही है।



जगदीश नेगी
भवाली, नैनीताल, उत्तराखंड

एंकर...एक कदम आगे बढ़कर भी बदला जा सकता है कोई भी नक्शा, उत्तर से बहने वाली शिप्रा नदी पर आखिर यह प्रयास किस दिशा में बढ़ा... सुनते हैं उत्तराखंड के नेगी से..



नीम, काली या करवन जीर्णोद्धार, वेटलैंड सफाई में प्रथम पहल



कुलदीप मीना, आईएएस
मुख्य विकास अधिकारी
बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश

बुलन्दशहर जिले में नीम, करवन, काली नदियां 14 ब्लॉक्स की 125 ग्राम पंचायतों से गुजरती हैं। नदियों के जीर्णोद्धार किनारों पर पेड़ लगवाने के बाद जलस्तर वृद्धि, प्रदूषण मुक्ति के प्रभाव आने लगे हैं नजर...

परियोजना...

जल संचयन के तहत नदी के किनारे बनायी गयी ट्रेंच के किनारे वृक्षारोपण का कार्य भी कराया गया, जिससे नदियों के किनारों का भी संरक्षण हो सके। पहले इन नदियों में सदैव जल प्रवाह बने रहने से खेतों की सिंचाई, पशुओं को पानी, भूजल स्तर सही रहता व उपयोगी भी था। विगत कई वर्षों से नदी में सिल्ट जमाव एवं जल कुम्भी के कारण वह मूल अस्तित्व ही भूल रही थी। अभियान के द्वारा मूल रूप देते हुए अविरल रूप से प्रवाहमान किया गया। नदियों पर कराये गये कार्य के उपरान्त नदियों में पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है।

काली नदी पर बनायी गयी ट्रेंच से भी ग्राउन्ड वाटर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। जल संरक्षण के उद्देश्य से नीम नदी, करवन नदी का जीर्णोद्धार एवं काली नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा सफाई का कार्य एवं मनरेगा योजना से किनारों पर ट्रेंच का कार्य कराया गया है, अवशेष पार्ट को द्वितीय चरण में लेते हुए 41 किमी की लम्बाई पर कार्य किया जायेगा।

नदी की सूरत बदलने और प्रदूषण से मुक्ति के लिए नमामि गंगे अभियान के तहत वेटलैंड बनाने हेतु बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके अन्तर्गत काली नदी पर 04 वेटलैंड बनाये जायेंगे। नदी पर वेटलैंड बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड सहारनपुर द्वारा किया जायेगा, जिसका प्रस्ताव नमामि गंगे को भिजवाया गया था अब प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। काली नदी पर सर्वे होगा फिर कार्य प्रारम्भ होगा। वेटलैंड बनने से नदी का प्रदूषित पानी प्राकृतिक तरीके से साफ होगा। नदी में वेटलैंड के बीच से होकर बहने वाला पानी प्राकृतिक रूप से साफ होकर जायेगा। यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा।

नदी में अवरोध होने से यहां आसपास के खेतों में जलभराव की समस्याएं भी दूर हो गई हैं। औद्योगिक डिस्चार्ज की रोकथाम के लिए भी प्रयास जारी है। जीर्णोद्धार के बाद जामुन, सागौन, बरगद, सहजन के पौधे लगाए गए हैं। इन कार्यों से करीबन 65 ग्राम पंचायतों के निवासियों को सीधे लाभ मिला है।



जारी है जल यात्रा कानपुर देहात में...

सेमी क्रिटिकल श्रेणी में ब्लॉक से निकाल कर पानी की अधिक से अधिक उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है और इस पर कैसे आगे बढ़ें...साल दर साल बदलने लगे हालात...



लक्ष्मी नागपुन, आईएएस
मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ),
कानपुर देहात



सौम्या पांडे, आईएएस
अतिरिक्त श्रम आयुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार

कानपुर देहात में भी पानी की वही कहानी, लेकिन इसे बदलने के लिए जब पहल हुई तो दृश्य बदल गया, आखिर कैसे...सुनते हैं...

वर्ष 2020 की भूजल स्तर संबंधी रिपोर्ट दर्शाती है कि 10 में से 7 ब्लॉक सेमी-क्रिटिकल श्रेणी में हैं। यहीं से जल संरक्षण और जल संचयन उपायों की गति तेज हुई और नतीजा मिला कि 1650 जल निकाय पूरे हो गए हैं या निर्माणाधीन हैं। इनकी करीबन 2400 करोड़ लीटर पानी की भण्डारण क्षमता है। साथ ही 160 करोड़ लीटर क्षमता के 72 अमृत सरोवर बने। इसके साथ ही 12 करोड़ लीटर क्षमता वाले 618 सरकारी भवनों (ग्रामीण और शहरी) में छत पर वर्षा जल संचयन किया गया।

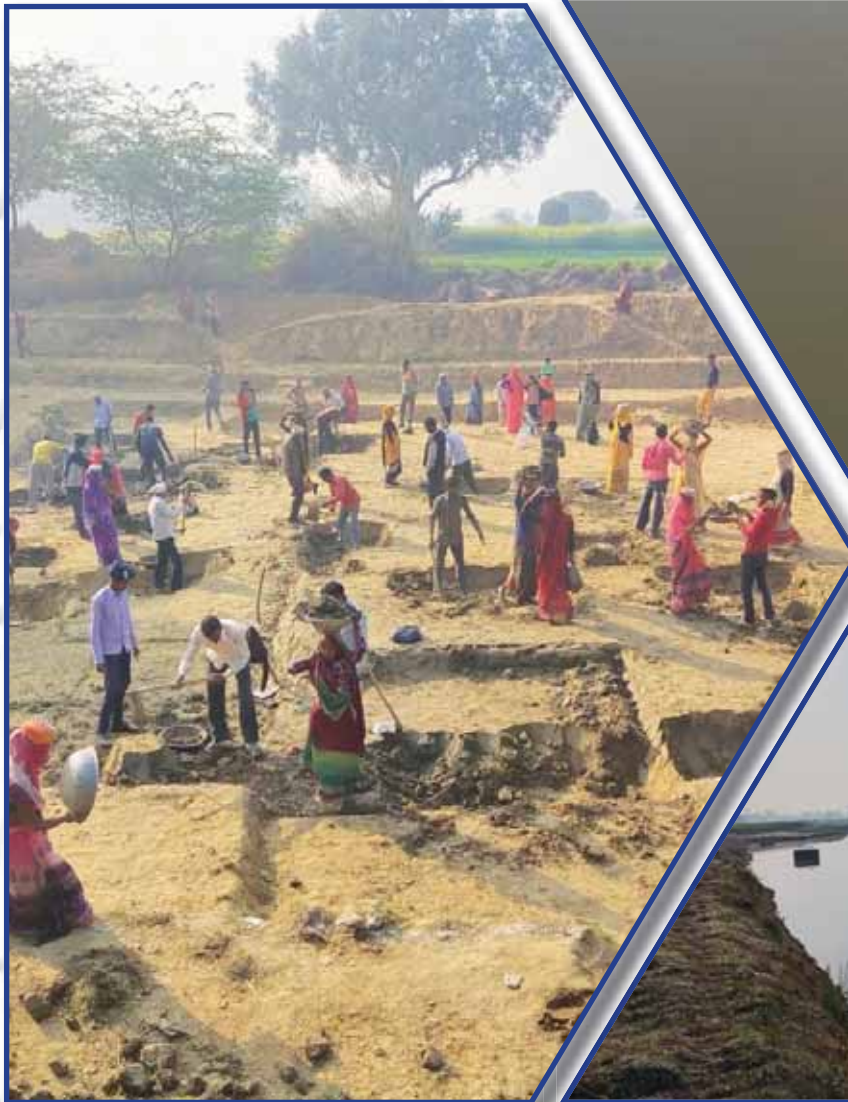
पांडु और नून नदी का पर्यावरण-पुनरुद्धार हुआ इससे भी 1528 हेक्टेयर भूमि पुनः प्राप्त की गई। ड्रिप और स्प्रींकलर सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके समुदाय, व्यक्ति से 217 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी। इन कार्यों से प्राप्त अतिरिक्त लाभ मिट्टी की नमी संरक्षण, पशुओं के लिए पीने का पानी, अतिरिक्त अपवाह से अतिरिक्त भंडारण, बाढ़ सुरक्षा, हरित क्षेत्र विकास, भूमि सुधार और विभिन्न जल संबंधी गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के अवसर बने हैं।

जिलों की विभिन्न नदियों पर कुल 43 चेक डैम प्रस्तावित हैं और 35 करोड़ लीटर पानी की भंडारण क्षमता और 1.1 हेक्टेयर की वार्षिक पुनर्भरण क्षमता के साथ पांडु नदी पर 1 चेक डैम पूरा हो गया है, जिससे 46 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ी है। अब तक नदी के किनारे 1 किमी के रैखिक विस्तार में भूजल स्तर 1-2 मीटर बढ़ गया है। पेड़ों और तालाबों के बिना कोई भी पुनर्भरण प्रणाली सफल नहीं होती है और इसके लिए जिले में लगभग 45.36 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में 113.4 करोड़ लीटर की कुल भंडारण क्षमता वाले 72 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। जिलों के 10 ब्लॉकों में कुल 5175 वृक्षारोपण के साथ अमृत वाटिकाएं भूमिगत जल को धारण करने और उनकी क्षमता के लिए पुनर्भरण संरचना को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में हैं।

जीआईएस आधारित योजना के तहत कुल 3223 जल निकायों की मैपिंग की गई और मैप किए गए सभी जल निकायों का अद्यतनीकरण 1047 गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 2908.77 हेक्टेयर है। इसके अलावा 599 वेटलैंड्स में से रसूलाबाद ब्लॉक की 9 परियोजनाओं के अनुसार जिलों में 2.25 हेक्टेयर से अधिक की 187 वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था।

जिले ने 3.45 करोड़ की भंडारण क्षमता वाले खेत तालाब बनाए हैं। नदियों के पुनर्जीवन के प्रयासों से किसानों और संबंधित ग्राम पंचायतों के निवासियों में समृद्धि आई। सेंगुर नदी के पुनर्जीवन के समान प्रयास जलग्रहण क्षेत्र के उपायों जैसे कि पेड़ लगाना, बीज बोना, समोच्च खाइयाँ, मिट्टी और नमी संरक्षण द्वारा किए गए थे। जिले की 72 प्रतिशत भूमि कृषि उपयोग के अंतर्गत है और 17 प्रतिशत निम्नीकृत वन, बंजर क्षेत्र, झाड़ीदार भूमि और निम्नीकृत चारागाहों के रूप में बंजर भूमि है।

जेजेएम के तहत जल संरक्षण और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ग्रामीण आबादी को शिक्षित करने के लिए विभिन्न जन संवेदीकरण कार्यक्रमों के साथ जल उपयोग दक्षता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।



संभल जिले में जमीन पर उतार रहे नदियां



मनीष बंसल, आईएएस
जिला अधिकारी, बहजोई,
संभल, उत्तर प्रदेश

नदियां भी गुम हो सकती हैं... उससे बड़ा साहस है कि अतिक्रमण से गुम हुई नदियों को खोज निकाला, एक तो बह रही है दूसरी जल्द जमीन पर दिखेगी...

यूपी के मुरादाबाद मंडल का संभल जिला उन पिछड़े जिलों में से एक है जहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। जिले में कोई नहर नहीं है और किसान केवल भूजल और वर्षा पर निर्भर हैं। मध्य गंगा नहर सिंचाई प्रणाली अभी भी निर्माणाधीन है। जिले में मौसमी नदियां सोत और महवा सिंचाई और जल निकासी के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थीं।

ये दोनों नदियां कई साल पहले विलुप्त हो चुकी थीं। वर्ष 2019 में सोत नदी को पुनर्जीवित करने के कुछ प्रयासों के बाद, अतिक्रमण और लोगों की उदासीनता के कारण नदी अभी भी विलुप्त थी। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद जिलाधिकारी संभल बनने के बाद इस परियोजना पर काम किया गया।

मानचित्रों और जमीन पर नदी के मार्ग की पहचान करने के लिए 5 ब्लॉकों और 71 गांवों में टीमों का गठन किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अधिकारियों को तैनात किया गया और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक अधिकारियों ने मनरेगा के तहत कायाकल्प का काम शुरू किया।

काम नवम्बर-2022 में शुरू हुआ और जुलाई 2023 तक 100 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 1.7 लाख से अधिक मानव दिवस काम कर, पसीना बहाकर नदी को जीवन देने के लिए आगे बढ़े। वर्ष 2023 की बरसात में संभल जिले की पूरी नदी पानी से लबालब हो गई। इससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही क्षेत्र में भूजल स्तर भी बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में सोत नदी के कार्य की सराहना से प्रेरित होकर अब महवा नदी के पुनरुद्धार पर भी कार्य प्रारम्भ करने की योजना बना रहे हैं।

इस कार्य का सामाजिक प्रभाव और करीबन 70 गांवों के लोगों को लाभ हुआ है। वहीं देश, व दुनिया भर में यह योजना एक प्रेरणा बनी है।



आपको ये जानकर
खुशी होगी कि साल के
पहले 6 महीने में ही ये लोग
नदी के 100 किलोमीटर से
ज्यादा रास्ते का पुनरोद्धार कर चुके थे।

जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहां के लोगों की
मेहनत रंग लाई और सौत नदी, पानी से, लबालब भर गई।
यहां के किसानों के लिए यह खुशी का एक बड़ा मौक़ा
बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे बांस के
10 हजार से भी अधिक पीछे भी लगाए हैं, ताकि
इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहे।



संजली
बात
94 698961, 9222



परंपरा से जी जाएंगे जल स्रोत और जलाशय...

पारंपरिक जल प्रबंधन, जल की संस्कृति...

जब क्लाइमेट चेंज का घना साया दुनिया पर छाने लगा तो ध्यान आया कि हमारी अपनी पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की परंपराएं तो इतनी समृद्ध हैं कि उन्हें कलमबद्ध कर लिया जाए तो हमारा अपना समाज स्वयं ही इस वैश्विक संकट से निपट लेगा। बस, इसी लगन में पूरा देश घूम डाला। गांव-गांव जाकर लोगों से बात की। प्राचीन जल संरक्षण के रूप में बिखरे तालाबों, जोहड़ों, कुइओं, नाडियों, कुंडों को जाना, समझा और कलमबद्ध किया। परम्पराओं से लहलहाता पर्यावरण, इस दिशा में एक और प्रयास जल्द एक किताब के रूप में आ रहा है।



डॉ. मीना कुमारी जागिड़
ट्रेडिशनल वाटर प्रैक्टिशनर,
दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली

पारंपरिक बातें जो इतिहास की किताबों के पन्नों में अभी समेटी नहीं गई थीं को जानने व समझने कीकि कहीं ये कालजयी परंपराएं इतिहास न बन जाएं, मन को यह डर सताता रहा। यही जल धारा बह निकली और अब इसी से आज कई जलाशय दोबारा जीवित हो गए...

बीते कुछ दशकों से गांवों से पलायन हो रहा है। शहर हर दिन विकराल, और विकराल होते जा रहे हैं। उनके मन में इस स्थिति को बदलने की आग है। इसी का हल निकालने के लिए दिल्ली छोड़कर राजस्थान के कोटपुतली क्षेत्र, जहां कभी नदी नाले बहते थे और अब वहां के लोग पीने के पानी को तरसने लगे हैं। भूजल स्तर गिरता जा रहा था। खेती बाड़ी, पशुपालन सब अस्त-व्यस्त होने लगा लोग पलायन बढ़ने लगा।

बच्चों को महिलाओं को विशेषकर इस कार्य में शामिल किया। जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। गांव के पारंपरिक जलाशय और उनका आगौर कितने क्षेत्र में, कौन कौन सी वनस्पति उस क्षेत्र में होती थी जिससे तालाब के पायतन को मजबूती मिलती थी तो जल सालभर स्वच्छ बना रहता हो इसके सर्वे किए।

देश भर के प्रमुख शोध संस्थानों एवम् विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन पर व्याख्यान से जल चेतना जारी है। शोध यात्रा कर पारंपरिक जल प्रबंधन की परंपराओं को, लोकसंस्कृति को जाना समझा, साथ ही उस क्षेत्र के विषयों विशेषज्ञों से जानकारीयां जन जन तक पहुंचाना है। आजादी से पूर्व देश के स्थानीय शासकों की क्या जल नीति रही, जैसे राजस्थान में जलाभाव नहीं रहा वहीं बिहार समाज कभी बाढ़ में नहीं डूबा, उसपर गहन शोध किया गया। अब राजस्थान, गुजरात में पारंपरिक जल की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए स्कूली बच्चों व ग्रामीणों का जलाशयों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हेतु जमीनी प्रयास कर रही हैं। साथ ही अपनी परंपराओं को याद दिलाते हुए जलाशयों का पुनर्जीवित एवम् साफ सफाई के कार्य कर रही हैं। विशेषकर कोटपुतली के पावटा क्षेत्र में दस जलाशयों को पुनर्जीवित किया गया, इससे वहां का जल स्तर बढ़ा और सबसे अच्छी बात हुई कि ग्रामीण अपने जलाशयों को स्वयं ध्यान रखने लगे हैं।

निवास-राजस्थान, मूल निवास-सादुलपुर तहसील, चूरू, राजस्थान

रूचि, शैक्षणिक योग्यता-इतिहास में डाक्टरेट, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। वर्ष 2016 में कोटा विश्वविद्यालय से चूरू मंडल का पारम्परिक जल प्रबंधन विषय पर पीएचडी। शोधकार्य में गहन अध्ययन करते हुए थार मरुस्थल का परंपरागत जल प्रबंधन पर पहली किताब लिखी। जिसके तीन संस्करण आ चुके हैं। आईसीएचआर के प्रोजेक्ट बीकानेर राज्य की जल व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन : 1701 ई. से 1950 ई. में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं।

हेतु सर्वेक्षण किया। वर्तमान में मीना देश की प्रमुख सामाजिक संस्था, दीनदयाल शोध संस्थान के तीन प्रोजेक्ट में पिछले पाँच वर्षों से एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट जल संस्कृति पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ, दूसरा, पोषण संस्कृति पर बिल व मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और तीसरा, सुजलाम्, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ कर रही है।

थार मरुस्थल का परंपरागत जल प्रबंधन चूरु मंडल के विशेष संदर्भ में

मीना कुमारी



Engineer flows the water across the borders



Niimalan Raghavan
Thanjavur, Tamil Nadu

Niimalan Raghavan, an Engineer by profession and quit his job in Dubai and move back to Nadiyam to dedicate his life to improving his homeland, why his work telling to the world..

Niimalan Raghavan, an Engineer by profession is now an organic farmer and a social activist. Nimalan was born in an agricultural family, in Nadiyam village close to Thanjavur district in Tamil Nadu. At 31 years of age, in 2018 he was devastated by the havoc left behind by the Gaja cyclone in his hometown. That day he decided to quit his job in Dubai and move back to Nadiyam to dedicate his life to improving his homeland.

He developed a natural tendency since childhood to connect with others, be empathetic and be more aware of others' needs. His active participation in NSS camps and social awareness programs further ignited his passion to help others and shaped him to be more socially responsible. His passion is to conserve and rejuvenate water bodies while raising awareness in his community.

He has successfully restored 172 water bodies across India and 3 in Kenya and planted 16.20 lakh saplings, created 400+ Miyawaki forests, recharged 200+ failed borewells also trained farmers on sustainable farming practices. He has restored waterbodies as big as 620 acres and the minimum size is 2 acres, he has so far restored 7000+

acres, which has so far served 60 lakh+ beneficiaries from 2500+ villages.

Nimalan uses modern techniques to restore the water bodies, therefore long-time sustenance is ensured. He has won several awards and he also recently won the Better India's Water Warrior award, his work was selected among 1700+ participants across India. Most of his waterbody restoration projects are crowdfunded and are sustainable. All waterbody restoration project includes afforestation too. Improving green cover serves as the heart of our project, this is to imply the close link between water and trees. He plants only native variety saplings to restore the ecosystem. He is now restoring lakes from Kanyakumari to Kashmir. Recently, he also started restoring lakes in working for African countries.

Social Impact of Work...
So far more than 60 lakh people benefited from 2500 Villages got benefited. Most of the beneficiaries are fisherman and farmers. To ensure the maximum water capacity is conserved through water body restoration (1 acre can hold 1.5 crore litres of water).





प्रशांत गाडेकर, आईआरएस
आयकर आयुक्त, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

पुणे के केदुर गांव
की 16 हजार की आबादी
पानीदार बनी, टैंकर से पानी
पीने वाले गांव को टैंकर फ्री
बनाने की यह कहानी जिसे
रचने के लिए आगे कई
हाथ।

पानीदार केदुर गांव, टैंकर विलेज से टैंकर फ्री विलेज

केदुर महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तालुका में एक बड़ी ग्राम पंचायत है। गांव की कुल आबादी लगभग 16,000 है। कृषि (सब्जियां, प्याज, बाजरा, दूध प्रमुख उत्पाद हैं) डेयरी प्रमुख आजीविकाओं में से एक है। बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाले कुल सात सूक्ष्म जलक्षेत्र हैं। गांव के पश्चिम और दक्षिण में सह्याद्री पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं और वर्षा जल का बहाव बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। 1972 के सबसे भीषण अकाल के बाद समुदाय द्वारा परकोलेशन और भंडारण टैंक और गांव में झीलों के निर्माण का व्यापक अभियान चलाया गया।

यहां करीबन 400 मिलीमीटर बारिश होती है और मानसून में ही यहां पानी आता है। 2018 में यहां साल में 177 एमएम बारिश हुई जिससे सूखा पड़ गया, लोग पलायन करके दूसरे स्थानों पर जाने लगे। यहीं से मैंने काम करने का संकल्प लिया।

सबसे पहले पानी साक्षरता अभियान जलाया, जलदूत बनाए जिन्होंने जागरूकता फैलाई की गांव को पानीदार बनाने पर पूरा ध्यान दिया। ड्रोन की सहायता से समूचे नक्शे बनाए और सातों माइक्रो वाटरशेड की पैदल यात्रा की। देशा यहां छोटे-बड़े-मध्यम 38 तालाब गाद से भरे मिले। 32 किलोमीटर का नाला भी गाद से भरा हुआ था उसे पूरी तरह से साफ करवाया। इसके लिए ग्रामवासियों की टोलियां बनाई और काम शुरू किया। यहां करीबन 70 हजार सेपलिंग्स प्लांट किए गए और गाद निकालकर उसका सदुपयोग किया गया। वर्ष 2022 में बारिश में लगभग 500 एमएम से अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद ही गांव टैंकर फ्री कहलाया...। इन कार्यों में लोगों ने योगदान दिया, आरपी फाउंडेशन पुणे ने सहयोग किया। कल्याणी भारत, मानवलोक ने मदद की। डॉ. सुमंत पांडे ने पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया और सुश्री अंजलि कोटकर, मस्कविता शिंदे और शुभाअम्बेगेट ने पूरे कार्यक्रम में अमूल्य सहयोग दिया।

बदली तस्वीर...

- परकोलेशन और अन्य टैंकों से कुल 1,99,000 क्यूबिक मीटर गाद निकाली गई
- कुल 32 किलोमीटर जलधाराओं को लगभग तीन मीटर गहरा औसत 10 मीटर चौड़ा किया जिससे 4,80,000 क्यूबिक मीटर गाद निकली।
- लगभग 70 करोड़ लीटर भंडारण क्षमता बढ़ी।
- वाटरशेड का तीन गुना रन ऑफ जितना था।
- कुल 4,395 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई सुनिश्चित की गई।
- पहले गांव की पहचान टैंकर वाले गांव के रूप में होती थी अब वह टैंकर फ्री गांव है।
- करीबन 16,000 की जनसंख्या को लाभ हुआ और दो हजार से अधिक डेयरी पशुओं को लाभ हुआ।
- 30 प्रतिशत खेती योग्य क्षेत्र को दो सुनिश्चित फसलों के अंतर्गत और 10 से 15 प्रतिशत को तीन फसलों के अंतर्गत लाया गया।
- किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि में गाद डालने से अच्छी फसल और अच्छी आय हुई।
- गाद का उपयोग करके तीन किलोमीटर आंतरिक सड़कों को मजबूत किया गया।

पाणीदार केंदूर येथील पिंपल खोरी मधील पाझर तलावचे
खोलीकरण व गाल काढण्याचे काम झाल्याले मोठ्या प्रमाणात
पाणीसाठा वाढला आहे आणि ते पूर्ण क्षमतेने भरले आहे।



पाणीदार केंदूर येथील पिंपल खोरी येथे खेड सिटी व भारत
फोर्स कंपनी च्या माध्यमातून दीन भाती बंचार तयार
करण्यात आले आहे आणि ते पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत।



सौंदर्य से पहले श्रम के रंग, चली नदी बदलकर रंग

गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, गोमती से 20 से अधिक शहरों को पानी मिलता है लेकिन जब यह गाद से भरी, अतिक्रमण का शिकार थी तभी एक कदम ऐसा पड़ा कि 51 दिन बाद, 47 किमी, तीन हजार लोगों के श्रम ने पूरे इलाके को खुशहाल कर दिया..।



पुल्कीत खार, आईएस
एसीओ, जीएनआईडीए,
ग्रेटर नोएडा

लखनऊ वालों गोमती नदी से पीने का पानी मिलता है, गोमती रिवरफ्रंट फेवरेट स्पॉट है। लेकिन जहां से यह नदी निकली, वहां यह गुम थी...। पीलीभीत में फुलहर झील से यहां तक का सफर आखिर कैसे तय किया...।

पीलीभीत जिले की माधोटांडा पंचायत में गोमत ताल या फुलहर झील से एक शांत उद्गम वाली यह नदी, गाजीपुर जिले के सैदपुर में गंगा नदी से मिलने से लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इंडियन जर्नल ऑफ इकोलॉजी में प्रकाशित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गोमती का प्रवाह खतरे में है।

पड़ोसी जिला शाहजहांपुर में प्रवेश से पहले नदी उद्गम जिले में यात्रा केवल लगभग 47 किलोमीटर है। गोमती नदी 16 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है लेकिन पूरा रास्ता बाधाओं से भरा है। पहली नजर में नदी दिखी ही नहीं थी। पुनरुद्धार एक चुनौती थी, अतिक्रमण, गाद, खरपतवार की वृद्धि और स्वामित्व की कमी शुरुआत में प्रमुख समस्याएं थीं।

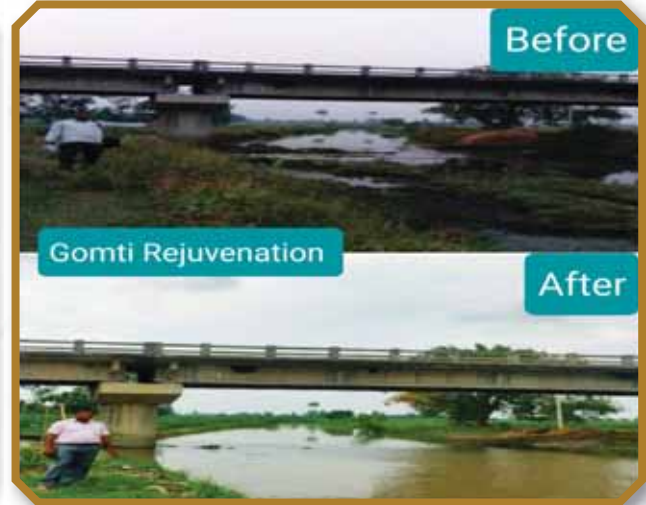
पंचायतवार नक्शे बने, बैठकें हुईं, तराई बेल्ट होने के नाते, भूजल स्तर की कमी नहीं थी। मनरेगा में परियोजना बनी, सभी 16 ग्राम पंचायतों में चौड़ीकरण और गहरीकरण का काम शुरू हुआ, उसे मानसून से पहले पूरा भी करना था। मां, गोमती नदी पुनर्जीवन कार्य मजदूरों, ग्रामीणों में जोश था। जोश में कमी दिखी तो जिला मजिस्ट्रेट रहते पदयात्रा की और खुद दौरा किया। ग्रामीणों के साथ चलते हुए स्थानीय ज्ञान से कई समाधान किए। गांव दूसरी समस्याओं का भी हल किया। औसतन 3000 से अधिक मजदूरों ने 51 दिनों तक काम किया। चैनल को चौड़ा और गहरा करने के लिए खुदाई के दौरान तराई के उच्च भूजल स्तर बढ़ा, काम के दौरान सांप निकलने से भी कुछ दिनों तक दहशत का माहौल रहा।

गर्मी उमस के बीच बरसात में परिणाम दिखना तय था। नदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए ढाल बनाए रखने की योजना पर काम करना था। नदी से सटे किसानों से स्वेच्छा से अपनी मातृ नदी के लिए रास्ता बनाने में मदद मांगी गई। परिणामस्वरूप, किसी भी अतिक्रमणकारी किसान ने नदी चैनल की चौड़ाई में सुधार के कार्याकल्प प्रयासों पर आपत्ति नहीं जताई और नदी से सटे खेतों के चिन्हित 513 किसानों को नदी में गिरने वाले रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के बहाव को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया गया।

इन क्षेत्रों में पंपों को हतोत्साहित किया गया जबकि ट्रेंचिंग को प्रोत्साहित किया गया। प्रसिद्ध जलविज्ञानी डॉ. कृष्णास्वामी से सलाह ली गई। उन्होंने सलाह दी कि खेतों से पानी के बहाव को कम करने से खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जिसने नदी के प्रवाह को काफी हद तक रोक दिया है। पूरी नदी में ग्रास-कार्प, विभिन्न प्रकार की मछलियां भी शामिल की गईं। अवैध मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और पुलिस विभाग की ओर से ऐसी पारिस्थितिक रूप से हानिकारक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी लागू की गई। गाद किनारों पर जमा हो गई, यह वापस न जाए इसके लिए उसे जलजमाव की शिकायत वाले स्कूलों के मैदानों में भेजा।

राजस्व रिकॉर्ड से नदी के किनारे स्थित 23 तालाबों की पहचान हुई और उन्हें भी पुनर्जीवित किया गया, ताकि वे नदी के लिए जल भंडार के रूप में कार्य कर सकें। चौड़े किए, सीढ़ियां बनाई और एक पिकनिक स्पॉट बनाया ताकि वहां जीवंतता बनी रहे।

नदी जिन 16 ग्राम पंचायतों से गुजरती वहां 16 घाट बने और अब नदी के किनारे के ग्रामीणों के लिए रोजाना सुबह योग कक्षाएं और शाम को गोमती आरती होती है। नदी के किनारे होने वाली इन गतिविधियों से ग्रामीणों का नदी के साथ जुड़ाव और जुड़ाव बेहतर होता है और नदी को साफ रखने का उनका संकल्प मजबूत होता है। इन सभी गांवों में प्रबंधन समिति का गठन कर दिया गया है। वे प्रवाह को बनाए रखने के लिए उनकी नियमित बैठकें करते हैं, गलती करने वाले ग्रामीणों को सलाह देते हैं, सुधारते हैं और फटकार भी लगाते हैं जिनके कार्यों से नदी की शुद्धता या प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहां साइनेज लगे हैं, त्रिवेणी घाट, गोमती गुरुद्वारा और एकोतारनाथ मंदिर जैसे कुछ प्रमुख भूमि चिह्नों की पहचान की गई थी जिन्हें अब गोमती पर्यटन सर्किट के हिस्से के रूप में उजागर किया जा रहा है। नदी के किनारे कुछ भोजनालय और रेस्तरां भी चिह्नित किए गए थे। उदगम स्थल या उद्गम तालाब को भी पिछले वर्ष एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। साल के जंगलों से घिरे इस सुंदर स्थान में नौकायन, भोजनालय, बच्चों के लिए मनोरंजन और शाम को नियमित गोमती आरती की सुविधाएं पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। पर्यटकों के लिए इस स्थान को टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व से पर्यटक वाहनों को किराए पर लिया गया है।





रामबाबू तिवारी, जल योद्धा
अंधाव, बबेरू, बाँदा, उत्तर प्रदेश

यूपी के प्रयागराज जिले में शंकरगढ़ क्षेत्र व समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन, जल के प्राकृतिक स्रोतों तालाबों, छोटी नदियों संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गांव- गांव पानी चौपाल, पानी पंचायत, नदी संसद के आयोजन रंग ला रहे हैं...

पति से कीमती पानी जहां, जल स्रोतों को जीवन मिलता वहां...

समूचे क्षेत्र में 56 तालाबों का जीर्णोद्धार पूरे बुंदेलखंड में अब तक करवाया गया है। इसमें छत्तरपुर जनपद में नीति आयोग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 23 तालाबों का जीर्णोद्धार गौरिहार ब्लॉक में हुआ। मनरेगा में 45 तालाबों का खुद की देखरेख में जीर्णोद्धार कराया गया है। खेत तालाब योजना के तहत 13 खेतों में 13 तालाब बनवाए गए। तीन तालाबों से अतिक्रमण हटवाया जा चुका है।

बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद के अंतर्गत मां मंदाकिनी गंगा संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विगत 5 वर्षों से संघर्षरत। मंगल ग्राम की अवधारणा से 11 गांव में नानाजी देशमुख से प्रेरित होकर गांव में प्रकृति केंद्रित विकसित हो रहे हैं।

जल संवर्धन के लिए खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, अभियान के तहत खेत पर मेड़बंदी बनाने का कार्य किया जा रहा है इस अभियान की सराहना प्रधानमंत्री मन की बात के कार्यक्रम में सराहना भी 27 जून 2021 में कर चुके हैं। मेड़बंदी का कार्य 10 गांव में 5000 से अधिक बीघे में बारिश की एक-एक बूंद को रोकने के लिए खेत पर मेड़बंदी करवाई गई। पेड़ जियाओ अभियान के तहत 50,000 से अधिक की संख्या में खुद के हाथों द्वारा वृक्षारोपण किया जा चुका है। पूरे बुंदेलखंड में 5000 से अधिक जल सेवक बनाए जा चुके हैं और जल से जन को जोड़ने के लिए प्रदेश स्तर की तीन पानी यात्राओं का नेतृत्व किया।

भूजल का स्तर बढ़ा है। ईंधन की खपत कम हुई है-गांव में ट्यूबेल समरसिबल से नहीं कुछ तालाबों से सिंचाई हो रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हुआ, फसल का उत्पादन बढ़ा है। धान, गेहूं की फसल होने लगी हैं। पेयजल की समस्या में सुधार हुआ है। गांववासियों में सामाजिक समरसता का माहौल बन रहा है।







Ruhail Maqbool Sheikh

Water quality analyst from
Srinagar, Jammu and Kashmir

Water is life. In Kashmir we have multiple water sources including rivers, springs, groundwater but still what required one person understand and started working to trained community to-day picture is chnaged...

Water is life now community understanding verry well

Kashmir have multiple water sources, but is threatened by overdevelopment, global warming, lack of awareness and pollution. People living in rural, now aware on water conservation, these communities understanding the value of water and ill effects of pollution, actively practising water conservation techniques, cleaned all water bodies, using environmental friendly products, and as per records there is no case of water borne diseaes reported so far after these practices followed by them.

Water is life. We have multiple water sources in Kashmir including rivers, springs, groundwater etc. These sources have been used for hundreds of years, but is threatened by overdevelopment, global warming, lack of awareness and pollution. In the past, the water quality in Jammu and Kashmir was practically perfect and devoid of pollution. As a result of anthropogenic activity, the water quality in many places is now potentially dangerous to human consumption and health. I have Started an awarness drives in kashmir on water conservation, management, sanitation, water quality issues, waste management etc since more than ten years i am involving in these practices,wherei have trained thounds of people including sarpanchs,teachers,womens,young,old,villagers etc. And i am glad to say that majority of the people trained so far are now well aware of water conservation and other environmental issues and are practising things and suggesting others as well.

Social Impact of Work.....

People especially living in rural, far flung areas are less aware on water conservation and other techinques or practices thus resulting in pollution of water bodies, water borne diseases, and other environmental issues, Hence to aware these communities is challenging is need of the hour, since i started making these communities aware and to understand the value of water and ill effects of pollution, and i am glad to share that after revisting these places i found these communities were actively practising water conservation techniques, they along with volunteers cleaned all water bodies, they are now using environmental friendly products, and i am happy to say that as per records there is no case of water borne diseaes reported so far after these practices followed by them. Also waste management practices are also followed by most of the communities i have trained so far.



तकनीक से मिल रहा पानी, डेढ़ करोड़ को मिला जीवन, समृद्ध हुई किसानी



एस. कृष्णा चौतन्य, आईएस
कमिशनर मनरेगा,
भोपाल, मध्य प्रदेश

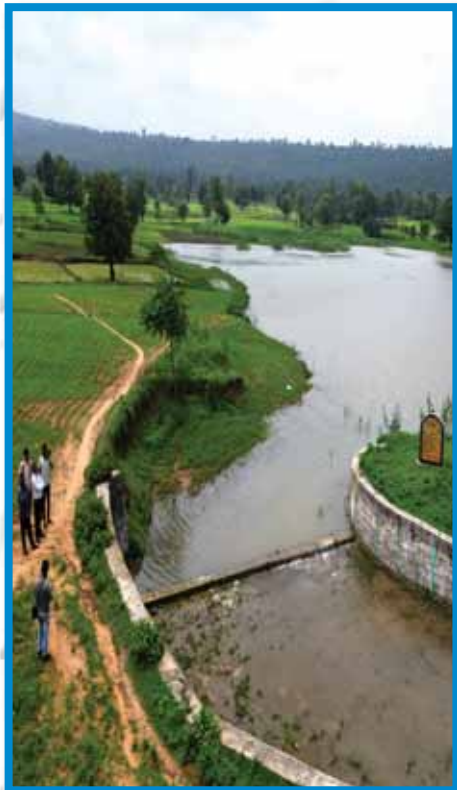
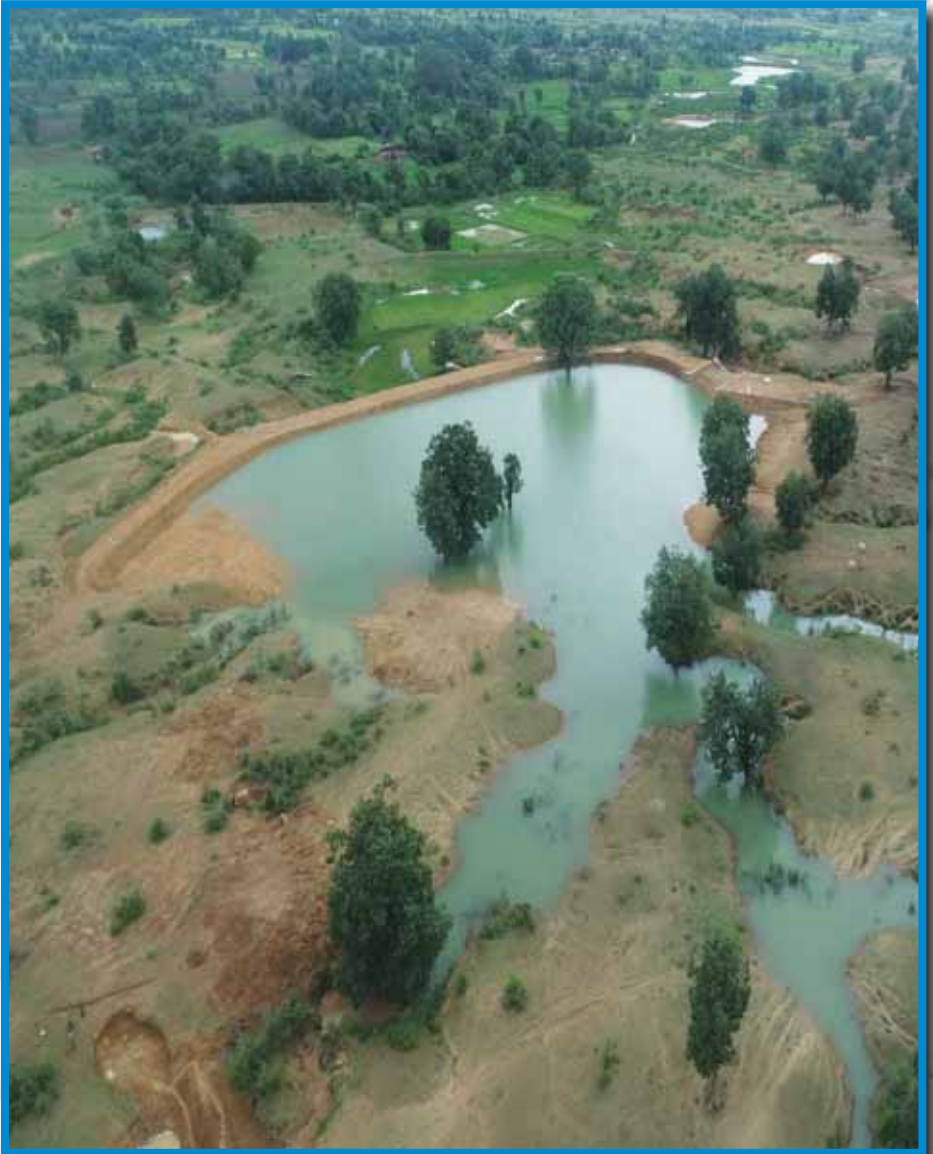
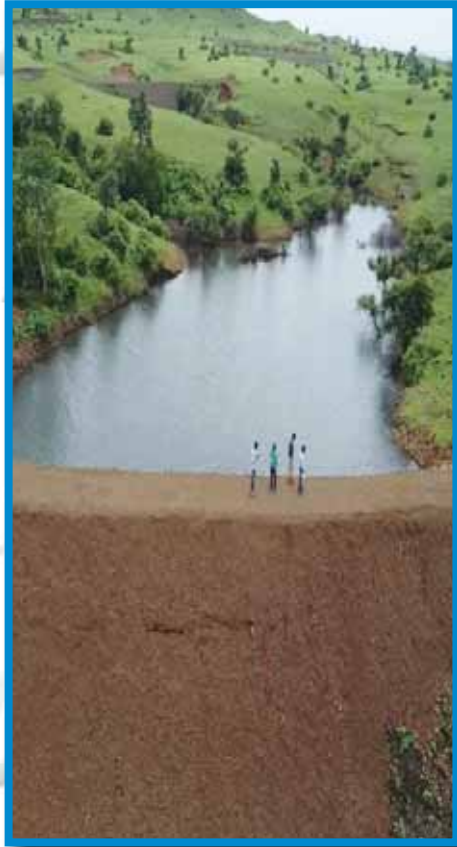
**जीआईएस
आधारित योजना
बनाई, इंजीनियर्स को
प्रशिक्षित किया, 81
ब्लॉकों में काम शुरू
किया, 5100 तालाब
खड़े हो गए। करीबन
डेढ़ करोड़ लोगों को
आखिर कैसे मिला
पानी...**

मध्य प्रदेश में जल संरक्षण कार्य 2019 में सावधानीपूर्वक जीआईएस आधारित योजना के साथ शुरू हुआ। इसे ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजटिंग तंत्र के इष्टतम उपयोग के साथ मनरेगा के तहत अनुमत एनआरएम कार्यों के योजनाबद्ध कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना प्रक्रिया में सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट का विकास शामिल है, इसके बाद एमजीएनआरईजीएस के सभी तकनीकी पदाधिकारियों की आसान समझ के लिए गूगल अर्थ प्लेटफॉर्म पर सभी एनआरएम और गैर-एनआरएम गतिविधियों के लिए जीआईएस आधारित योजना का विकास शामिल है।

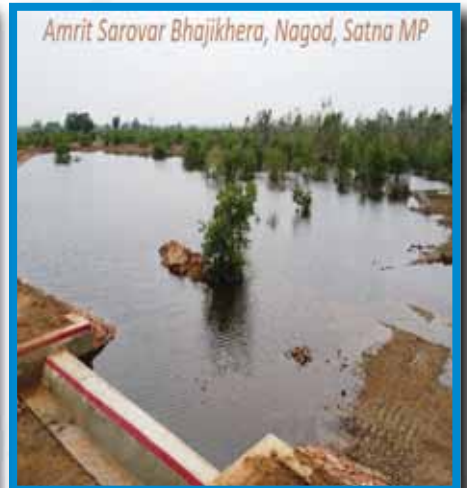
यह पहल प्रत्येक जिले की दो-ग्राम पंचायतों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना और कैच द रेन अभियान में की गई गतिविधियों के संबंध में संबंधित भूवैज्ञानिक इलाकों में इस खतरे को कम करने के लिए प्रभावी समाधान विकसित करना है। इसके बाद मनरेगा के तकनीकी कर्मचारियों को उनके संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए जीआईएस आधारित योजना की बुनियादी प्रक्रिया पर प्रशिक्षित किया गया, एमजीएनआरईजीएस के 2000 से अधिक इंजीनियर्स को प्रशिक्षण देकर। कैच द रेन के तहत विकसित संरचनाओं ने राज्य के ग्रामीण हिस्सों के निवासियों के लिए पानी की उपलब्धता को काफी समय तक बढ़ा दिया गया, परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि के विकास में मदद मिली है और लोगों के लिए अतिरिक्त आजीविका पैदा हुई है।

इन योजनाओं ने न केवल पानी के संरक्षण की दिशा में काम किया, बल्कि कार्यान्वयन के माध्यम से व्यक्तिगत गांवों की भूमिहीन महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए मिट्टी की नमी और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण गतिविधि के कार्याकल्प भी किया। मध्य प्रदेश में पहली बार ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश भारत में 81 जल संकटग्रस्त ब्लॉकों (3 श्रेणियों अतिदोहित, गंभीर, अर्ध-गंभीर में विभाजित) वाला क्षेत्र है, सभी ब्लॉकों में काम शुरू हुआ और 19650 संरचनाओं की पहचान की गई और काम किया गया।

प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण का मिशन शुरू हुआ और एमपी में 5900 से अधिक नए तालाब लिए व 5100 से अधिक तालाबों का निर्माण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश ने जीआईएस आधारित डेटा को एक समान पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के लिए एक राज्य का अपना पोर्टल विकसित करने पर भी काम किया है, जो सभी के लिए उपलब्ध है। एमपी ने अटल भूजल योजना में भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पीएचईडी की एकल ग्राम योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पानी की स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने मजबूत योजना तंत्र के माध्यम से संबंधित विभागों का भी समर्थन किया है। इन सभी क्रियाकलापों से करीबन डेढ़ करोड़ लोगों को सीधे लाभ पहुंचा है।



अमृत सरोवर तालाब - ग्राम पिपरिया ग्राम पंचायत फिफरी



Amrit Sarovar Bhajikhera, Nagod, Satna MP

Story of Ponthampuli Village

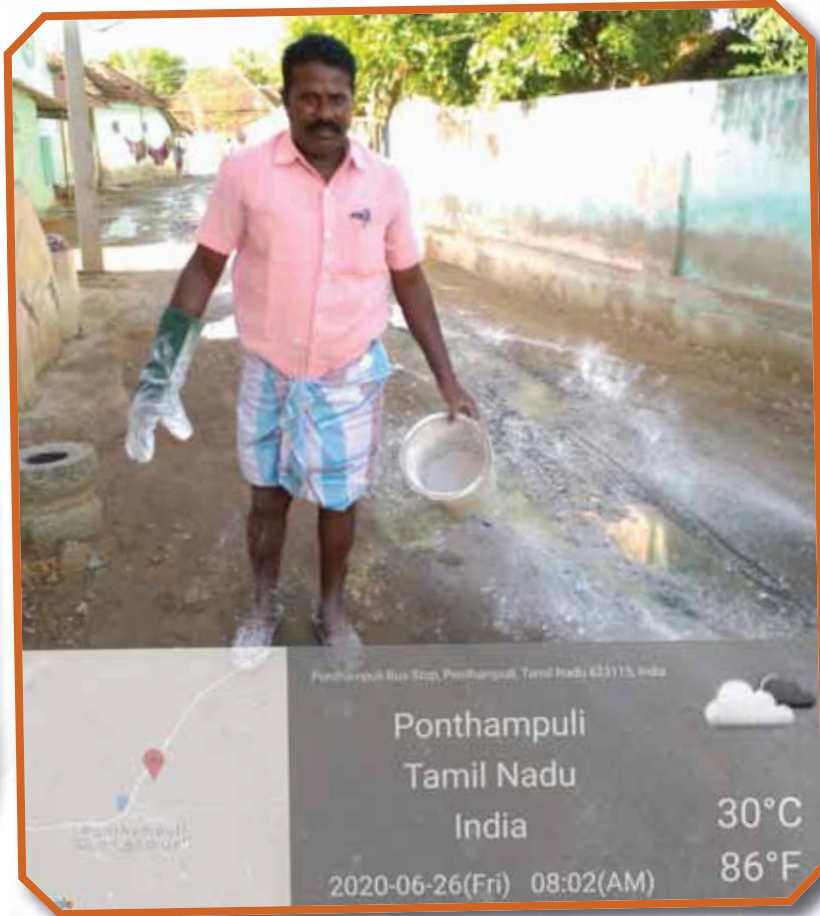


S. Arumugam

Vice President
Ponthampuli Gram
Panchayat, Kamuthi,
Tamil Nadu

The Ponthampuli village is located near the Coastal area minimum of 10 km. this Village is one the UNOPS Implementation Village. Usually, Ramanathapuram district has a very dry and water scarcity area so people migrate to other districts like Thirrupur, Coimbatore, Erode and Chennai. Because here no livelihood opportunities are low in agricultural work. But Ponthampuli village has a good groundwater level because of the Vice President's initiatives he improved that village in water conservation. He removed Prosopis juliflora from all the water bodies in Ponthampuli village. He increased private Agricultural ponds. If there was any emergency he supplied water to the people by his vehicle. Every 10 households have a street pipeline. He reduced Migration and planted more than 3,000 trees around the irrigation tank.







Sharad Aggarwal
Sector Head, Project Finance
Group, ICICI Bank Limited



Shailesh Chandra Jha
AGM, ICICI Bank Limited

ICICI Bank has a legacy of caring for ecology and environment. Water conservation has been one of the focus areas with objective of improving/enabling accessibility of water by sustainable interventions and thereby improving the quality of life and increase in the income levels of the underprivileged.

Bank who deposit happiness in water bodies

ICICI Bank has a legacy of caring for ecology and environment. As a part of promoting sustainable livelihoods in rural areas, Water conservation has been one of the focus areas with primary objective of improving/enabling accessibility of water by sustainable interventions and thereby improving the quality of life and increase in the income levels of the underprivileged. In view of the fact that livelihood of the villagers are impacted due to non availability of adequate water at the appropriate time that further leads to migration, health & hygiene issues, suicides and associated issues such as education, early marriages of children, etc., watershed management activities have been undertaken in the villages prone to droughts, floods or water scarcity due to its topography or low and erratic rainfall or dry spells due to the effects of climate change. With the objective of making the villages self sufficient in water and generating sustainable livelihood opportunities, in the form of direct or indirect employment, in the villages, various initiatives have been undertaken.

The initiatives at village level included dissemination of information on importance of water conservation and best practices through program and workshops to create awareness among the local villagers for sustainable water conservation by community participation and involvement;

supporting creation of water holding structures like construction of ponds, recharge pits, percolation tanks, low cost wells and water holes for recharging of streams/rivulets/ springs/ other water bodies to enable percolation of water for recharging of groundwater thereby increasing the water storage area that can be used for aquaculture and enabling fisheries production that would result in increased availability of nutritional food besides generating employment among the villagers;

installation of roof top rain water harvesting systems that collects the water from the rooftops and injects the water into bore wells/wells leading to recharge of aquifers leading to increase in ground water level and availability of water for a longer period for domestic purposes thereby enabling improved hygiene and cleanliness and reducing dependency on tanker water; rejuvenation of water bodies (small lakes, ponds, first order streams) through de-siltation, removal of weeds, deepening and widening that has helped in controlling floods and soil run off, improving quality of water due to oxidation, availability of aquatic vegetation; constructing check dams, compartment/farm bunding, trenching, and gully plugging

has resulted in improving the soil surface to enable reduction in erosion of the fertile top layer of the soil and help retaining the moisture.

The interventions also included plantation of local fruit and fodder plants in the catchment areas to increase the green cover which further helps in water percolation to recharge ground water and also controls soil erosion. The impact of the aforesaid initiatives is visible in and around the project sites.

These interventions in an organized manner has resulted in upgrading the socio economic status of the population in the form of self sufficiency in water leading to sustainable agriculture and livelihood due to increased availability of water for domestic use, increased availability of water for livestock and wild animals, increased availability of water for irrigation, improvement in quality of soil, increase in soil depth, increased area of cropping, increased cropping intensity, increased crop diversification, availability for water bodies for aquaculture and fisheries production and providing employment opportunities,

ICICI Bank supported villagers to install rooftop rainwater harvesting systems. In collaboration with Poornam Ecovision Foundation and MAPS Industries (I) Pvt Ltd. The Bank has supported the installation of the systems in 100 village across nine talukas in Beed district. In the district, over 4500 structures now use rooftop rainwater harvesting systems. These structures cover more than 38 lakhs sq. feet of rooftop area, with the potential to inject 26 crore liters of water into the ground annually. The initiative makes these villages self-reliant on water.

After the implementation of Rooftop Rainwater Harvesting project, the water table in these villages will rise every year by approx. 28 crore liters of rooftop rainwater.



शिक्षक का नया पाठ, जो गांव को बना रहा पानीदार

जल संरक्षण आंदोलन में पच पाटिल

मिशन 500, जल संरक्षण एक जन आंदोलन है। जल प्रहरी डॉ. उज्जवल कुमार चव्हाण के संकल्प पर मिशन छह वर्षों से सामाजिक संगठनों और जनभागीदारी के माध्यम से जल बचत के लिए काम कर रहा है। इस मिशन को जमीन पर समर्पित, प्रशिक्षित और निस्वार्थ पच पाटिल टीम द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। महाराष्ट्र के 13 जिलों के 125 गांवों के किसानों को एक साथ लाए और सामाजिक संगठनों की मदद से मिशन ने 500 करोड़ लीटर पानी बनाने का लक्ष्य पूरा किया।



शेखर नारायणराव निंबालकर
मिशन 500, चालीसगांव, महाराष्ट्र

मिशन के पच पाटिल में से एक....। मैंने सतमाला रेंज की तलहटी में 30 गांवों में 85000 हेक्टेयर के त्रिकोणीय बेसिन में मिशन लागू किया। गांव के क्षेत्र में नालियों और नदियों को खोदना, गाद निकालना, बहते पानी को रोकने और उसे जमीन में रिसने के लिए सीसीटी अवशोषण गड्ढे बना रहे हैं। इन गांवों में लगभग 150 करोड़ लीटर का जल भंडार निर्मित है। इन गांवों के किसानों के साथ जल संरक्षण करते हुए 45000 देशी पेड़, बांस लगाए हैं। इस क्षेत्र में 15 किलोमीटर कृषि सड़कों का निर्माण किया गया।

यह क्षेत्र डोंगरी और तितुर नदियों का नदी बेसिन है, जहां मुख्य रूप से लामन वंजारी प्रवासी लोग निवास करते हैं। ये लोग मानसून के बाद गन्ने की कटाई के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं। अपने ही गांवों में पानी की उपलब्धता के कारण वे दो मौसम में खेती कर पाते हैं, गांवों में 8-9 महीने रोजगार मिलता है, पानी आया तो पलायन कम हुआ है। इस कार्य का सकारात्मक पहलू यह है कि प्रवासन कम होने से बच्चों की शिक्षा छोड़ने का अनुपात कम हो गया है।

पेशे से एक शिक्षक हूँ, मुझे बच्चों को फिर से स्कूल जाते और उनके नामांकन में वृद्धि देखकर खुशी होती है। मैं रविवार और छुट्टियों में मिशन के लिए समय निकालता हूँ, सामाजिक संगठनों की मदद लेता हूँ, किसानों के प्रशिक्षण और प्रेरणा का समन्वय करता हूँ। मिशन के तहत कई सम्मेलनों में यह विधा चर्चा में आई। किसानों के बीच जागरूकता पैदा की। वर्धा में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस के हाथों सम्मानित किया गया। मुझे डोंगरी नदी के नदी समन्वयक के रूप में सरकारी जीआर, चला जुनुया नदीला, में शामिल किया गया है।



Jalsanjeevini : A unique project



Shilpa Nag, IAS
District Collector,
Chamrajnagar, Karnataka

Jalsanjeevini is the process of planning works based on natural resource management under Ridge-to-valley principle, using geospatial technology to complement the planning of water conservation based works.

This unique program to identify the catchment area in the gram panchayat and divide it into three parts as upstream, intermediate and downstream, use geospatial technology to scientifically identify the required works, know at what stage which works are appropriate and according to the water budget, based on the available resources, this unique program will implement the works to the full extent for a period of three years. It will play an important role in water conservation.







श्रुति शर्मा पाण्डेय, आईएएस
पूर्व जिला अधिकारी, फतेहपुर
और वर्तमान में एसीओ, YEIDA

सूरज पटेल, आईएएस
सीडीओ, फतेहपुर

कानपुर, इलाहाबाद और गंगा-यमुना के बीच फतेहपुर में जल संकट न हो यह ध्यान में रखा और सर्वोदय के आदर्शों पर चलते हुए नोन नदी, तालाबों को पुनर्जीवित किया। अमृत सरोवर के 3,400 स्रोत पानीदार किए, नदी खुदाई से 100 स्रोत पानीदार हुए। जिससे करीबन 85,000 लोगो को पानी मिला, इलाके की रंगत बदल गई।

बहता पानी है समृद्धि की निशानी : नदी हो या तालाब दे दिया उसका निखरा स्वरूप

यमुना नदी के कछार क्षेत्र में सहायक नदी के रूप में प्रवाहित नोन नदी कानपुर देहात के मूसानगर से चलकर फतेहपुर के अमौली, पचौरा ग्राम से प्रवेश करती है। यहां 23 किमी तक 10 ग्राम पंचायतों एवं 16 राजस्व गांव से होते हुये चांदपुर गांव के पास यमुना नदी में जा मिलती है। बरसात में यह बहती और गर्मियों में सूख जाती। दशकों पहले नदी में कृत्रिम जल स्रोत थे जिससे पूरे साल बहती जिससे किसानों, पशु, पक्षियों, जानवरों का यहां कोलाहल दिखता। दो दशक पूर्व नदी में गाद भरने से प्रवाह रूक गया, कृत्रिम स्रोत प्रभावित हो जाने से यह पूरी तरह सूख गयी। दोनों तटों पर रहने वाले किसानों के सामने सिंचाई, जानवरों, पशुओं के सामने पेयजल का संकट खड़ा गया। ग्रामवासियों और किसानों अपने स्तर पर छिटपुट प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली।

26 मई 2023 को नोन नदी पुनर्जीवन के लिये जिला अधिकारी ने बैठक की, नदी की खुदाई का पुनीत कार्य प्रारम्भ हो गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं जनसहभागिता से खुदाई एक महीने में पूरी हो गई। खुदाई के बाद नदी में पानी देखकर लोगों में खुशी एवं उल्लास की लहर दौड़ गई। नदी पुनर्जीवन से अन्न उत्पादन में वृद्धि होने की प्रबल सम्भावना बढ़ी है।

खुदाई के बाद यहां किनारे की मिट्टी का कटान रोकने के लिये दोनों तरफ 10 हजार वृक्ष रोपित किए गए जो ऑक्सीजन, जीवन, स्वच्छ वातावरण के लिए सहायक होंगे।

नदी बह रही है और इससे विकास खण्ड अमौली के ग्राम केवटरा, भरसरा, कहिंजरा, इटरा, बदलू का डेरा, सदलू का डेरा, मरवाही का डेरा, सिकन्दरपुर, औरा निस्फी, गौरी औरा सहित कई गांवों के लोगों सहित करीबन 50 हजार की आबादी को लाभ मिला। इससे न केवल विकास खण्ड अमौली डार्क जोन की सूची से बाहर आ गया, बल्कि जल संचयन की क्षमता में 552 मिलियन लीटर की वृद्धि भी हुयी, सिंचाई की सुविधा हुई, पशु पक्षियों को पीने हेतु जल भी मिला।

इसी तरह 209 अमृत सरोवर बनवाए जिनमें औसतन 1,672 मिलियन लीटर जल संचयन क्षमता की वृद्धि हुयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-गर्भ जल स्तर ऊपर आया है एवं औसतन 66 मिलियन लीटर जल संचयन क्षमता में वृद्धि हुयी है। खेतों की सिंचाई के क्षेत्रफल में भी विस्तार हुआ है।

बांके बिहारी मंदिर स्थित जलाशय (गंगा सरोवर) सन् 1730 ई0 में स्थापित श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित तालाब अपने अस्तित्व और दुर्दशा का शिकार था। अतिक्रमण से आच्छादित तालाब की करुण पुकार जिला प्रशासन के कान तक पहुंची तो गाद निकालकर यहां बाउन्ड्रीवाल निर्माण, लाइट्स लगवाई और आज यह स्थान गंगा भक्तों के लिए पूजनीय स्थल है। ज्वाला देवी मंदिर परिसर रमणीय अमृत सरोवर फतेहपुर जिले के बिन्दकी तहसील में प्राचीन मां ज्वाला देवी मंदिर परिसर में 300 सालो से जीर्णोद्धार अवस्था में अनुपयोगी पड़ा प्राचीन पक्का तालाब था। आज यहां सुंदर, पानीदार तालाब है और आसपास के लोग आकर शाम-सुबह आनंदित होते हैं।

जिले में किए गए कार्यों से आम जनमानस के साथ ही पालतू पशुओं, पक्षियों के साथ-साथ जंगली पशुपक्षियों को लाभ हुआ। अमृत सरोवर से लगभग 3,400 स्रोत पानीदार हुए एवं नदी की खुदाई से 100 स्रोत पानीदार हुए। लगभग 85,000 लोगो को पानी उपलब्ध हुआ।



भारत-पाक सीमा पर जन्मा जल प्रहरी, धरती मां की कोख में चाहे अपार शुद्ध जल भंडार



सुनील प्रभाकर
फिरोजपुर छावनी, पंजाब

पंजाब में जल
संरक्षण के लिए
प्रयास रंग लाए
लेकिन अभी खेती
बदलने के प्रयासों
से लेकर कई मोर्चों
पर काम करना
होगा, ताकि धरती
में भूजल को बढ़ा
सकें...

हिंद-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे पंजाब के सरहदी जिला फिरोजपुर में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पत्रकारिता में हाथ हाजमा रहा था की तभी जल संरक्षण की ओर ध्यान गया। पढ़ा तो देखा, समुद्र की रक्षा के लिए उस समय युद्ध हुआ और सवाल आया कि आखिर अब इस युद्ध को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने पढ़ा तो सोचता रहा कि कलयुग में जल योद्धा परशुराम कौन है कलयुग में तो हमारे देश में लोकतंत्र है फिर समुद्र नदियों तालाबों की रक्षा के लिए युद्ध किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाए।

मैंने सीखा लोगों में जागरूकता और समुद्र नदियों तलाबों भूजल की रक्षा के लिए पर्यावरण विरोधी हकूमतों के खिलाफ सत्याग्रह किया। विश्व बैंक की तरफ से करोड़ों रुपए गांव-गांव में बने तालाबों पोखरो को पुनर्जीवित करने के लिए भेजा गया। अधिकारियों को समझाया कि जब तक गांव के लोग पानी के संस्कारों से परिचित नहीं होंगे, जल के प्रति अपने रिश्ते को नहीं समझेंगे कोई भी धनराशि लगा दो नदियां, तालाब फिर एक साल में गंदे हो जाएंगे।

हमें यह काम करने का मौका दिया कि आप गांव-गांव में लोगों को जागरूक करें तालाबों को साफ करने के लिए श्रमदान करने के लिए। इस दौरान दर्जनों गांव में गांव वालों के साथ चौपाल बैठकें की उन्हें समझाया कि तालाब धरती के गलफड़े हैं, बारिश के पानी को धरती के नीचे पहुंचाते हैं और भूजल का संतुलन बनाए रखते हैं। हमारी अलख जगाने का यह असर हुआ की दर्जनों गांव में लोग उठ खड़े हुए। फरीदकोट के दर्जनों गांव में हजारों गांव वालों ने श्रमदान किया और अपने गांव के तालाबों को साफ किया और मशीनरी का खर्चा सरकार ने दिया। गांव वालों ने अपने तालाबों को गोद लिया और असर नजर आया।

पंजाब के 12650 के करीब गांव मे से करीब आधे गांव घूमे जहां कई जगह असर दिखा। पंजाब के कई जिलों में जल प्रहरी खड़े हो गए ऑर्गेनिक खेती करने लगे। लेकिन पंजाब में पानी के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाना होगा।



ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਥਰਿੰਡਾ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 1300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਤਰਾ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 11% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 22% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 71% ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 403 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੁਨੀਲ ਪੁਰਾਕਰ, ਘ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿਲਪ ਸਿੰਘ ਆਰ ਸਿੰਘ ਭੇਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ



ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਅਗੁਦੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਟ ਸਕਾਰਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੋਜੀਵਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ

ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਬਾਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2,80,000 ਵਾਹੀਯੋਗ ਚਮੀਨ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਲ-ਕਾਰਕੁ

ਤੋਂ ਜੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ





कर्नल सुरेश पाटिल
पूर्व सैनिक, पुणे महाराष्ट्र

भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद ग्रीन थंब पर्यावरण संरक्षण समूह बनाकर पिछले तीन दशकों से पूरे भारत में और पुणे, महाराष्ट्र जलवायु अनुकूलन अभियान को विस्तार दिया। वर्ष 2012 अप्रैल से हमने खडकवासला बांध से गाद निकालने और इसके जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण शुरू किया है।

जवान, करे समृद्ध किसान, खेत खलिहान

वयोवृद्ध सुरेश पाटिल ने अगस्त 1993 में सेवानिवृत्त होने के बाद भारत में पानी की कमी से लड़ने के लिए काम शुरू किया और पुणे में खडकवासला बांध के कार्याकल्प का काम से पहल हुई। इसके बाद डी-सिल्टिंग परियोजना देश के लिए एक रोल मॉडल बनती जा रही है।

भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद ग्रीन थंब पर्यावरण संरक्षण समूह बनाकर पिछले तीन दशकों से पूरे भारत में और पुणे, महाराष्ट्र जलवायु अनुकूलन अभियान को विस्तार दिया। वर्ष 2012 अप्रैल से हमने खडकवासला बांध से गाद निकालने और इसके जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण शुरू किया है।

पूरे अभियान में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट पर विशेष फोकस किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाद झील में न गिरे। अब तक समूह लगभग पच्चीस लाख ट्रक मिट्टी निकालने में सफल रहे हैं और इसे वृक्षारोपण और बड़े पैमाने पर जनता और किसानों के लिए वितरण के लिए उपयोग कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी (किसानों, एनसीसी कैडेटों सहित) के साथ वृक्षारोपण कर रहे हैं, एनएसएस स्वयंसेवकों, रोटरी के सदस्यों, लायंस क्लब और स्कूल और कॉलेज के युवाओं ने अब तक लगभग पंद्रह लाख पेड़ लगाए हैं। हम प्रत्येक एक पौधा एक अभियान के तहत प्रति पुणेवासी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हैं।

यह एक सामूहिक परियोजना रही है। सीएसआर फंड यानी कमिंस इंडिया फाउंडेशन, टाटा मोटर्स, एसकेएफ, मुकुल माधव फाउंडेशन का प्रयास, पुणे शहर और पुणे जिले के लगभग 250 गणपति मंडल, बीईजी दक्षिणी कमांडेंट भारतीय सेना से प्रशिक्षण मोड में इंजीनियरिंग प्रयास, जिसमें पुणे के छोटे योगदान भी शामिल हैं और प्रकृति प्रेमियों ने इसमें योगदान दिया।





Rejuvenation of Manganga....

The three rivers namely Man, Korda and Afruka converge and flow near our village. I had always felt affection and gratitude towards these rivers since childhood and therefore, after retirement, I decided to work for river Man ganga, situated in Dist Satra, Solapur and Sangli of Maharashtra.

We traveled the entire length of the Manganga river in the year 2010 and 2015, along with a colleague on foot and recorded the observations of the riverbed; Man River is originating in Satara district and runs 165 km through Satara, Sangli, Solapur districts.. We also found out the reasons for the deterioration of the river bed and published a detailed book on it. Thinking about how to rejuvenate the Man river, we established a trust namely, "Manganga Bhramanseva Bahuuddeshiy Sanstha Tal - Sangola" in the year 2014 and started cleaning the Manganga river through people's participation. Initially, efforts were made to clean the river bed at many places through Shramdan with the cooperation of schools, colleges and villagers in the river area. But we found that the existence of the river was threatened due to the silt stored in the K. T. Ware/ bunds and barrages and the trees and bushes like Chilar acacia, other noxious plants growing in the riverbed. The width of the river bed, which had a glorious width from 150 meters to 300 meters, was reduced and the river became like a drainpipe. So this task was huge and difficult. We were not able to get help from state government. We were also aware everybody derives benefits from river but some hardly pay attention towards it. So the task of cleaning the river seemed discouraging, but someone had to start so we started this task. Therefore, in the year 2015, Manganga river cleaning and revitalization work was started through Lok Sabhag (Peoples Participation). Through this work, the river bed became clean and wide and the positive results of that work started to be seen as water was stored.



Vaijinath Ghongde

A/P. - Wadegaon
Tah. - Sangola

**President-
Manganga
Bhramanseva
Bahuuddeshiy
Sanstha
Tal-Sangola.**

Our work attracted the attention of many organizations, individuals and villagers. The villages along the river started standing back helping as they can. We started cleaning the river bed of the villages every summer, and during other seasons we were contacting other villages, educating about cleanliness, getting people's participation for it and further working how the riverbed will get its original shape. From the last 9 years, a total of 75 km i.e. 53 km in Solapur district and 22 km from Sangli district, the river bed has been cleared of Chilar Acacia. 18 Kolhapur type bunds in this area have been cleaned. So the reduced water storage capacity of the dam has been restored. Due to the removal of silt and dirt from both sides of the river bed, the process of percolation of water has started and the nearby wells and bores have benefited from it. The river bed of the existing 31 km of river bank is built by lifting the silt from both sides of the river bed. So the silt released from K.T.

ware dam was given free to the farmers; 192 farmers benefited from it and they filled a total of 322 acres with silt and turned the fallow lands into fertile lands. 20 lakh cubic meters of silt was removed from 75 km river bed and 18 K. T. ware which increased the water storage by 200 crore litres. The water absorption by Chilar Acacia has saved a lot of wasted water. Due to this, the retention period of water in the dam has increased and the farmers in the area have started benefiting to a large extent. This work has been completed at a cost of 1 Crore 68 Lakhs as the entire work was done by the representatives of the organization by themselves with the help of crowd funding. Farmers spent a total of 97 lakh rupees for sludge transportation. A total of Rs 2 crore 65 lakh 80 thousand was spent through public participation. The government budget for this work may cost more than Rs. 9 crores. Such work is done at minimum cost and maximum usefulness. For this, social organizations, riverside villages, some companies (CSR) and individuals stood behind us and gave financial, mental support. The work is still required to be done for stretch of 37 km in satara district, which will be taken up this summer.

Thanks.....!!!!





यशु दीप सिंह, आईएफएस
कोटागढ़, हिमाचल प्रदेश

वन्य सेवा अधिकारी होने से उन्हें पता है वन, वन्यजीव और जल एवं वायु में क्या बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही एक नदी द्वारा जब रास्ता भूलते देखा तो जो किया...वह सम्मान के योग्य है...

कानाहन नदी, सिरसा नदी की एक छोटी सहायक नदी है। सिरसा नदी सतलज नदी की सहायक नदी है और यह बही के पास सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और अंत में पंजाब राज्य में रोपड़ के पास सतलज से मिलती है लेकिन यह रास्ता भूली और जब मिलवाया तो कई गांवों की किस्मत बदल गई।

भूली नदी जब रास्ता, किस्मत बदल दी करवा कर याद...

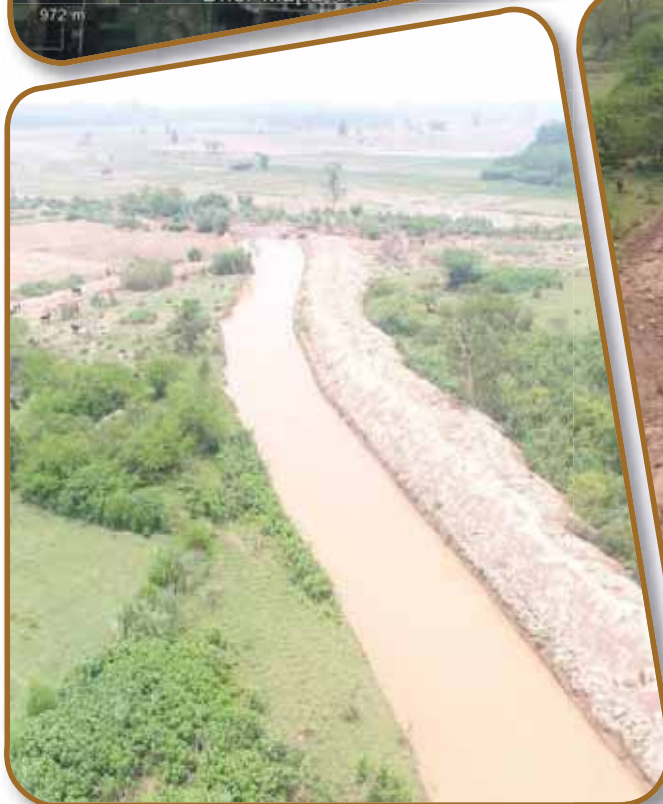
कानाहन नदी सोलन जिले के नालागढ़ तहसील में लखनपुर और झिरन जलग्रहण क्षेत्र से शुरू होती है और पंजाब में प्रवेश करने से पहले हिमाचल में नालागढ़ तहसील के मगनपुरा, मझौली और सैनी माजरा गांवों से होकर गुजरती है। पंजाब में कानाहन नदी के तल पर किसानों द्वारा खेती की शुरुआत और उसके बाद पिछले कई वर्षों (लगभग 30 वर्षों) से खेती की प्रथा के कारण, नदी ने पंजाब के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी अपना रास्ता खो दिया है। जिससे आज वह अपनी सहायक नदी सिरसा से नहीं मिल पा रही है। गाढ़ बड़ी तो गांवों में बाढ़ आ गई जबकि 1984-85 की गूगल फोटो में कानाहन नदी पंजाब में सिरसा नदी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई दिखाई देती है।

वर्ष 2020 में हिमाचल के अपस्ट्रीम गांवों में गंभीर बाढ़ के साथ-साथ वन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नालागढ़ वन प्रभाग ने उप वन संरक्षक, नालागढ़ की अध्यक्षता में मूल के कायाकल्प और पुनरुद्धार के कार्य के लिए योजना तैयार की। जून 2021 में कानाहन नदी का मार्ग और पंजाब की सीमा तक कानाहन नदी के मूल पथ को ध्यान में रखते हुए एक चैनल का निर्माण किया गया। चूंकि कन्हन नदी का मुख्य मार्ग संरक्षित वन भूमि में पड़ता था, इसलिए चैनल के किनारे से अतिक्रमण भी हटाया गया। कानाहन नदी के पुनरुद्धार का

मामला भी पंजाब में समकक्षों के साथ उठाया गया था क्योंकि जब तक नदी को अपने रास्ते का अधिकार नहीं दिया जाता है जब तक कि यह सिरसा नदी के साथ विलय नहीं होती, तब तक एच.पी. पर पुनरुद्धार का कार्य जारी रहेगा।

चैनल के बाद गांवों में बाढ़ नहीं आई और जुलाई 2021 के मध्य में बारिश के साथ ही पुनरुद्धार कार्य शुरू हुआ जो सफल रहा। पहली बारिश में ही नदी पर बने चैनल में पानी बहने लगा, रन ओवर द रिवर वॉटर तालाब भी बने। पंजाब की ओर कानाहन नदी के पुनरुद्धार के लिए काम शुरू होने की उम्मीद है।

वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नालागढ़ वन प्रभाग द्वारा जिला सोलन की नालागढ़ तहसील में हिमाचल प्रदेश की ओर लगभग 2 किलोमीटर तक कानाहन नदी के मार्ग का पुनरुद्धार किया गया। पुनरुद्धार के कारण वर्ष 2021 और 2022 में आसपास के गांवों (सैनी माजरा, मझौली गांवों) में बाढ़ में कमी आई। भूजल पुनर्भरण में मदद की, किसानों को नदी के पानी से सिंचाई में मदद मिली। पंजाब में कृषि प्रथाओं को खत्म करके या कानाहन नदी को उसका मूल मार्ग देकर इसे सिरसा नदी से मिलावाना है ताकि यह 40 साल पहले जैसे मिलती थी वैसे ही मिल सके। अभी जो कार्य हुए हैं उससे कई गांवों के लोगों को लाभ मिला है।





बोंगाईगाँव
BONGAIGAON

आपकी मुस्कान, हमारी प्रेरणा स्रोत YOUR SMILE IS OUR INSPIRATION



Powering progress goes beyond the generation of electricity; it encompasses empowering communities and nurturing a sustainable future. At NTPC Bongaigaon, Assam we not only generate 750 MW of reliable power, our commitment is to illuminate lives and drive positive change while upholding a healthy balance with the environment.

*Together, we kindle dreams and aspirations
for a brighter tomorrow.*

NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Bongaigaon Thermal Power Station

P.O. : Salakati, Distt. : Kokrajhar (BTAD),
Assam - 783369

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

Follow us ON : [f /ntpc1](#) [v /ntpc1td1](#) [t /ntpclimited](#) [in /company/ntpc](#) [n /ntpclimited](#) [n ntpc_limited](#)

Leading the Power Sector



हरित भविष्य को सशक्त करने की ओर अग्रसर

ऊर्जा क्षेत्र के वि-कार्बनीकरण के विजन के साथ चलने वाले संगठन के रूप में, पीएफसी राष्ट्र की हरित और सुचारु रूप से स्थायी भविष्य की ओर ले जाने की आकांक्षी यात्रा को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

ऊर्जा परिवर्तन के निमित्त हमारी शक्तियां



देश में नवीकरणीय/
हरित ऊर्जा के लिए
सबसे बड़ा ऋणदाता



पिछले 5 वर्ष में
32% का नवीकरणीय ऊर्जा
ऋण बही सीएजीआर



20,000+ मेगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा
क्षमता समर्थित



भारतीय विद्युत
क्षेत्र में सबसे
बड़ा ऋणदाता

54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड जारी करने की पात्र एक कंपनी



India's
energy
anchor



Image better, Drill deeper, Monetize faster.

Driven by India's vision of self-reliance in energy, **ONGC** is intensively pursuing Exploration in Deepwaters, Enhancing Production and Greening its Processes.

ONGC Jeetega
Toh Jeetega **India**

